The Indian Airlines Corporation carried out as many as 162 additional flights between Srinagar and Jammau Pathankot. They airlifted some four thousand passengers in addition to their normal flights.

Government are glad to report to the House that the personnel of the Armed Forces in addition to their assigned duties responded as citizens to the aid and succour of the afflicted people, voluntarily, and in considerable measure.

I, however, regret to inform the House that some twenty-two Army personnel lost their lives. I feel sure that the House would like me to convey to the next-of-kin and their families of these dead men our abundant sympathy, and also our appreciation of the prompt and spontaneous response of Army personnel in all ranks to render assistance to the civilian population—men, women and children—to the best of their ability

The account that has now been given, as required by this occasion, has to be restricted to the assistance rendered by the Armed Forces. The House is already aware both of the extent of damage and the extent of reparation and relief rendered by Governments, State and Central; and by voluntary authorities and organisations, both from the statements made in this House and from the reports that have appeared in the press.

Mr. Speaker: I am sure, as the Defence Minister has said, our sympathies go forth to the families of the twenty-two or twenty-three members of the Armed Forces who have lost their lives. We also appreciate the excellent work that has been done by the Armed Forces, and we hope that if necessary they will continue to do so.

12·16 hrs.

MOTION RE: RISE IN SUGAR PRICES

श्री कृष्णचन्द्र राय (खेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे सामने है उस को मैं उपस्थित करना चाहता हूं :

"कि यह सभा चीनी के वितरण के बारे में सरकार की नीति पर चिन्ता प्रकट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह चीनी के मूल्य में वृद्धि और चीनी के व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करे ।"

श्रीमान्, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर के मुझ को विवाद में हिस्सा लेने का अवसर दिया । साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री पार्लियामेंटरी अफेयर्स का भी आभारी हूं कि उन्हों ने इस विवाद के लिये समय निकाला ।

हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, सन् १९४७ में बनी थी और उस के बाद से दो साल ऐसे आये हैं कि जिन में शक्कर के मिल मालिकों ने और शक्कर का रोजगार करने वालों ने उपभोक्ताओं की पूरी पूरी लूट की । सन् १९४९ में ऐसा अवसर आया और उस समय भी इस सभा में इस प्रश्न पर विवाद हुआ था । उस समय हमारे वर्तमान मंत्री जी मंत्री नहीं थे । वह एक साधारण सदस्य थे जैसाकि मैं इस समय हूं । और उस समय उस विवाद में बोलते हुए उन्हों ने कहा था :

"The consumer was fleeced of no less than a sum of Rs. 6 to Rs. 8 crores, when the Government sat calling conferences, meetings, and committees, when every housewife was worried

[श्री सुखबक्त राय]

that she could not sweeten her child's milk with a pinch of sugar. Government was fiddling with committees, boards and conferences"

उस समय हमारे श्री अजित प्रसाद जैन ने उस समय की सरकार पर यह चार्ज लगाया था कि जब घर की औरतों को एक एक चम्मच चीनी नही मिलती थी उस समय सरकार कमेटिया, कानफरेसे और बोर्ड बुला रही थी । अब इस मार्च से ले कर इस समय तक मत्री जी ने जो शहरों और गावो के अन्दर चीनी के दाम बढे उस के बारे मे क्या किया । उस समय की सरकार ने तो कमेटिया, कानफरेसें और बोर्ड बुलाये थे । पर मत्री जी के मत्रालय ने तो इस बार कोई ऐसा नही किया ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) कमेटिया बन्द कर दीं ।

श्री सुखबक्त राय · कमेटिया बन्द हो गईं और कानफरेसे बन्द हो गई ।

सन् १९४९ में मत्री जी के अनुमान से ६ करोड ८ लाख रुपये की लूट की गई थी । इस समय जो अनुमान है उस के हिसाब से जो उपभोक्ताओं से मूल्य वसूल किया गया है शक्कर के मिल मालिको द्वारा और शक्कर के व्यापारियो द्वारा वह १५ करोड ८२ लाख आता है, जिस में से ७ करोड ४१ लाख तो मिल मालिको की जेब मे गया और जो उन से बचा वह थोक व्यापारियो और फुटकर के व्यापारियो की जेब मे गया । मैं कहना चाहता हू कि उस समय तो हमारे अजित प्रसाद जी को इतनी बडी चिन्ता थी, परन्तु इस समय जबकि १५ करोड रुपया उपभोक्ताओ की जेब से निकल गया और मिल मालिको और शक्कर के व्यापारियो की जेबो में चला गया, तो उन्हो ने कोई काम नहीं किया ।

सन १९४९ में जो शुगर रैकेट हुआ था उस के बारे में जांच कमेटी बनी थी और उस के सम्बन्ध में टैरिफ बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की थी । मैं माननीय मत्री जी से पूछना चाहता हू कि टैरिफ बोर्ड ने और उस कमेटी ने जो सुझाव दिये थे उन पर कितना अमल किया गया । जहा तक मैं जानता हू उन सिफारिशो पर कोई विचार ही नही किया गया और न अमल ही किया गया । उस समय टैरिफ बोर्ड ने सुझाव दिये थे कि किस प्रकार से शुगर रैकेट रोका जा सकता है । परन्तु जहा तक मुझे मालूम है, उन के मशुरावो पर आज तक कोई अमल नहीं किया । जो शुगर रैकेट सन् १९४९ में हुआ और जो इस साल हुआ जिस की मैं चर्चा कर रहा हू, इन दोनो में एक प्रकार की पारिवारिक समानता है । सन् १९४९ मे भी यह बात फैलाई गई थी कि चीनी का अभाव है । दूसरी बात उस समय यह भी कही गई थी कि ५० हजार टन चीनी पाकिस्तान को निर्यात की जायेगी और आखिर मे यह कहा गया कि वह एक्सपोर्ट नही होगा । तो जैसाकि मैं ने कहा इस समय भी बनावटी अभाव की धारणा पैदा की गई थी और उस धारणा को प्रोत्साहन मिला ५० हजार टन के निर्यात की बात से । इस समय भी करीब करीब वही बात हुई । आप देखेंगे कि फरवरी से चीनी का उत्पादन घटने लगा । मिल मालिको ने उसी समय से ५ आना, १० आना, १ रुपया, डेढ़ रुपया फी मन के हिसाब मे कीमतें बढानी शुरू कर दी । उस समय, जैसाकि मैं ने कहा, पाकिस्तान को निर्यात करने की बात कही गई थी । इस समय भी एक लाख टन निर्यात करने की बात थी जिस का इस सरकार ने फैसला दिसम्बर सन १९५८ में किया था । मेरी तो समझ में नही आता कि जब फरवरी में सरकार को यह स्पष्ट रूप से मालूम हो गया था कि इस वर्ष का उत्पादन पिछले साल

के उत्पादन से कम होगा, मैं तो समझता हूं कि उन को यह दिसम्बर में मालूम हो जाना चाहिये था क्योंकि उनके पास इस के आंकड़े आ गये थे कि इस साल गन्ना कम हुआ है, और फरवरी के आंकड़ों से तो साफ ही हो गया कि इस वर्ष शकर का उत्पादन कम होगा, फिर भी जब ९ मार्च को माननीय मंत्री जी शुगर मिल एसोसियेशन में बोलने गये उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम ५० हजार टन का निर्यात करेंगे । यह जरूर कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम इस में थोड़ी तबदीली कर देंगे । परन्तु ५० हजार टन के निर्यात की बात उस वक्त भी मौजूद थी और उस को उन्होंने वहां बताया । इस प्रकार एक तो फरवरी से अभाव की बात चल रही थी कि इस साल उत्पादन कम होने वाला है और दूसरे ५० हजार टन निर्यात करने की बात थी । इन दोनो बातो ने बाजार में बुलिश इफेक्ट पैदा कर दिया और जब बुलिश इफैक्ट पैदा हो जाता है तो दो बातें शुरू हो जाती है, एक कारनरिंग और दूसरी होडिंग, जिस को हिन्दी में कुनियाना और एकत्रीकरण कहते हैं । जब ये दो बाते शुरू हो जाती है तो दाम भी बढते है और आप जानते हैं कि जो हमारे शकर के मिल मालिक है और जो चीनी के व्यापारी है वे कोई दूध के धोये नही हैं । वह तो सिर्फ इसलिये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा करे । हमारे मन्त्री जी के दिल मे भले ही अच्छे खयाल हो और वह खयाल उन्हो ने अक्सर इस सदन मे जाहिर भी किये है, स्पष्ट भी किये हैं शुगर इडस्ट्री के बारे मे, जिस के बारे मे मैं बाद को बताऊगा । लेकिन मैं यह शुरू में ही कह देना चाहता हू कि यह हमारे मिल मालिक और व्यापारी पैसा पैदा करने के लिये ही बैठे है, ये कोई फिलाआफिक विचार ले कर नही बैठे हैं कि वह इस बात की कोशिश करे कि उचित मूल्य पर चीनी वितरित की जाय । वह ऐसा खयाल तभी कर सकते हैं जबकि उन के सिर पर आप का कोड़ा हो ।

अब मैं आप को शकर के उत्पादन के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं । यह तो ठीक है कि पिछले साल से इस साल शकर के उत्पादन में कमी हुई है । इस साल का उत्पादन, जहां तक मुझको मालूम है, १९ लाख ४ हजार टन हुआ है । परन्तु इस के यह मानी नही हैं कि शकर की कोई कमी थी । आप देखें कि जो पिछले साल की बची हुई शकर थी वह लगभग ६ लाख ५८ हजार टन थी जिस में से ३ लाख १० हजार टन तो शकर मिलो के ही पास थी । उस के अलावा २,४८ हजार टन शक्कर बाजारों में थी । ऐसा नही होता है कि जितना स्टाक बाजारो मे हो, वह सारे का सारा १ नवम्बर के पहले बेच दिया जाये । जो स्टाक १ नवम्बर के पहले दुकानदारो के पास होता है, वह उन के पास रहता है । उस के बारे मे अन्दाजा यह है कि २,४८ हजार टन शक्कर बाजारों में थी । इस के अलावा ५० हजार टन शक्कर बन्दरगाहो मे थी । उस मे आप इस साल की चीनी जोडिये, जोकि १९,०४ हजार टन थी ।

यह आकडे मैं ने इडियन शुगर मिल्ज एसोसियेशन के पत्र "इडियन शुगर' में से लिये है । इस में दो लाख टन खडसारी भी जोड़िये । पिछले साल से इस साल खडसारी का उत्पादन कम हुआ और उस का भी एक कारण है, लेकिन दो लाख टन तो अनुमानत उत्पादन किया ही गया । इस सब को आप जोड़िये, तो आप के तास इस पाल की वितरणलायक शक्कर—एवेलेबल टोटल सप्लाई—२७,६१,८७८ टन हो जाती है । जहा तक मुझे याद है, इस साल का शक्कर का स्टाक एक साल को छोड कर पिछले सालो में किसी भी साल के स्टाक से अधिक है । जब इतना स्टाक है, तो अभाव का प्रश्न ही नही उठता । परन्तु जैसा मैं ने अभी चर्चा की, फरवरी से हमारी शुगर मिलो का उत्पादन घटा और तभी से यह बात बाजारो में फैलने लगी कि शक्कर का अभाव है । पहले तो यह बात मौखिक रूप से बाजारो में चलती रही और

[श्री खुशवक्त राय]

उस के बाद अखबारों में इस का प्रचार होने लगा । अखबारों में शक्कर की मार्केट रिपोर्ट्स आती है, उन में यह चर्चा होने लगी । २३ अप्रैल, १९५९ और २७ अप्रैल, १९५९ के "स्टेट्समैन" मे इस प्रकार की खबरों को छापा गया । २३ अप्रैल की कलकत्ता की न्यूज थी और २७ अप्रैल की हापुड़ की न्यूज थी और इन दोनों में यह बताया गया कि इस साल शूगर का बड़ा अभाव है । उस वक्त शक्कर के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार का अनुमान बीस लाख का था । वैसे साढ़े उन्नीस लाख का अनुमान किया गया था, लेकिन इन खबरों में बताया गया कि इस साल शक्कर साढ़े अठारह लाख होगी, इसलिये शक्कर के दाम बढ़ेंगे और शक्कर की कमी होगी । लेकिन हमारे मंत्री जी और उन के मंत्रालय ने इस धारणा को दूर करने की क्या कोशिश की ? कोई बात ऐसी मालूम नहीं पड़ी कि मंत्री जी ने या उन के मंत्रालय ने कोई भी विज्ञप्ति या कोई प्रकाशन निकाला हो कि कोई अभाव नही है, कोई कमी नही है और शक्कर के मूल्य बढ़ने की कोई जरूरत नही है ।

अध्यक्ष महोदय, आप को, और सदन के साथी सदस्यों को यह बात स्मरण होगी कि जब हम लोग पिछले सत्र में ९ मई, १९५९ को उठ रहे थे, तो आप ने कृपा कर हमारा एक कालिंग एटेंशन नोटिस मंजूर कर लिया था और उस समय उस पर चर्चा भी हुई थी । उस समय पहले हमारे मंत्री जी मौजूद नहीं थे । उस दिन डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने उस का जवाब दिया था और उन्हो ने यह बताया था :

"Although the production of sugar this year is likely to be somewhat less than that of last year, this year's production together with the carry-over from last year is sufficient to meet the requirement of consumption during the current sugar year".

मेरा आरोप यह है कि जो बात माननीय उपमंत्री जी ने इस सदन में ९ मई को कही, वह बात उन को फ़रवरी में कहनी चाहिये थी ।

एक माननीय सदस्य : उस से क्या फ़र्क पड़ता है ?

श्री खुशवक्त राय : फ़र्क पड़ता है । अगर उस समय यह वक्तव्य दिया गया होता, तो बाजार में भाव न बढ़ते । फरवरी के बजाय ९ मई को यह बात कही गई । जब ९ मई को इस सदन में यह वक्तव्य दिया गया, तो उस वक्त तक शक्कर के भाव बढ़ चुके थे, काफ़ी ज्यादा हो चुके थे और उस वक्त उस वक्तव्य से मूल्यो के घटाने में कोई सहायता नहीं मिली । मै इस बात में नहीं जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से मिल-मालिकों ने चोर-बाजारी की । उन्होंने बड़े अजीब अजीब तरीके चोर-बाजारी के निकाले । मैं यह बताना चाहता हूं कि उन मिल-मालिको ने भी, जिन की बड़ी धाक है, जिन का, जब हम *कांग्रेस मे थे, हम मान करते थे, वही किया,* जो और मिल-मालिको ने किया ।

एक माननीय सदस्य : क्या किया ?

श्री खुशवक्त राय : माननीय सदस्य *सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय कहा है ?*

मैं ने पहले भी कहा था कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन में यह बात कई बार कही है कि शक्कर का उद्योग एक बड़ा ही सुनियंत्रित उद्योग है—एक वैल-रेगुलेटिड इंडस्ट्री है । उन्होने यह भी कहा है कि हम ने शुरू से ले कर आखिर तक—गन्ने के मूल्य से ले कर शक्कर के मूल्य तक—हर चीज पर कंट्रोल कर रखा है । उन्हों ने कहा कि उन के पास कोई गुंजायश नहीं है । मै नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि जब यह मोस्ट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है—मैं समझता हूं कि यह वर्स्ट ब्लैक-मार्केटियर है—,जब यह एक वैल रेगुलेटिड इंडस्ट्री

है, तो सरकार के रेगुलेशन कहां चले गये जबकि शक्कर के मिल-मालिकों और व्यापारियों ने करोड़ों रुपये पैदा कर लिये और सरकार रेगुलेट नहीं कर पाई ।

१८-१२-५८ को माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में गन्ने की कीमत बढ़ाने का विरोध किया था और कहा था—

"Our present ex-factory price of sugar in U.P. and Bihar is Rs. 36 per md. and no mill can sell sugar—a particular quality of sugar, that is D-29—for more than Rs. 36 per md. If any factory sells at a higher price then it is an offence calling for heavy penalty".

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब सरकार की तरफ से डी-२९ की शक्कर का मूल्य ३६ रुपये निश्चित किया था और मिलें उस से ज्यादा कीमत पर शक्कर बेचती रही । और यह तथ्य मंत्री जी को मालूम भी था, तो भी सरकार ने क्या कार्यवाही की । आल इंडिया शुगर मिल्ज एसोसियेशन के वार्षिक अधिवेशन में मंत्री महोदय ने चेतावनी दी थी कि मिलों ने शक्कर ऊंचे भाव पर बेची है । वक्तव्य में उन्हों ने स्वीकार किया कि मिलो ने शक्कर ऊंचे मूल्यो पर बेची । मैं यह जानना चाहता हू कि उन के इतने बड़े आफेन्स के बारे में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सिर्फ चेतावनी ही थी और उस का फल क्या निकला । क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं थे कि वे इन मिलों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते ? सरकार ने न तो कोई प्रिवेटिव और न पीनल मैजर लिया । क्यों नहीं लिया ? मैं जानता हूं कि सरकार के पास अधिकार थे । अगर आप शुगर कंट्रोल आर्डर की धारा ५(२) को देखें, तो उस में इस बात की मुमानियत की गई है कि मुकर्रर कीमत से अधिक मूल्य पर शक्कर को बेचा जाये । इस के अलावा धारा ८(ई) को भी देख लीजिये । उस में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उस को मालूम हो जाये कि किसी ने ऐसा किया है, तो उस के स्टाक सीज किये जा सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी मिल के बारे में मंत्री महोदय को इत्तिला मिली थी, तो वह उस का स्टाक सीज कर लेते । अगर एक भी मिल का स्टाक सीज कर लिया गया होता, तो किसी भी मिल की हिम्मत न पड़ती कि वह चोर-बाजारी करें ।

अब मैं कुछ बात आप के डाइरेक्टोरेट आफ शुगर एण्ड वनस्पति के बारे में भी कहना चाहता हूं । मेरे पास समय की कमी है वरना मैं बहुत सी बात कहता, परन्तू फिर भी मैं दो बात जरूर कहना चाहता हूं । पिछले वर्षों में जब शुगर के कोटे रिलीज होते थे फ्री सेल के लिये आन अलाटमेंट आफ टेंडर्स, तो वह जिस महीने के लिये रिलीज होते थे, उस महीने के पहले हफ्ते में या उसके पहले वाले हफ्ते में इश्यू हो जाया करते थे, लेकिन आप देखिये कि इस समय जो कोटे रिलीज हुए हैं वह काफी देर देर में रिलीज हुए है । आप इस बात को सोचिये कि जब देश म इस बात की धारणा फैल चुकी थी कि शुगर की कमी है तो दो दिन, तीन दिन, छः दिन, सात दिन की देरी इस अभाव की बात को प्रोत्साहन देती थी कि आखिर यह देरी क्यों हुई ।

दूसरी बात देखिये कि पिछले साल से जो कोटे रिलीज किये गये है वह कम किये गये हैं खास कर के अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने के पिछले सालों के आंकड़ों को मिलाय तो देखेंगे कि मार्च और अप्रैल में जो कोटे रिलीज किये गये वह कम किये गये और इसका भी यह प्रभाव पड़ा कि लोगों के दिलों में खयाल पैदा हुआ, बाजार वालों के दिल में यह खयाल पैदा हुआ कि शक्कर की कमी

[श्री खुशवक्त राय]

है। मुझे आप से यह भी कहना है कि आपने शुगर के डाइरेक्टोरेट को जो यह अधिकार दे दिया है कि जो भी आये उसे एक वैगन दे दो, यह कोई बहुत मुनासिब बात नहीं थी। जो लोग शुगर का व्यापार करते आये हैं, उनकी एक धाक है, उनकी एक पोजीशन है, लेकिन जिन्होंने कभी भी शक्कर का व्यापार नहीं किया वे यहां से वैगन्स ले गये और ले जा कर चोर बाजार में उसे बेचा। आपने कोई इस बात का प्रयत्न नहीं किया और आप के डाइरेक्टोरेट से कोई इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया कि जिन लोगों को शुगर के कोटे आन टेण्डर दिये गये, उन के बारे में कोई नियन्त्रण रक्खा जाता।

Mr. Speaker: One hon Member need not be too ambitious to exhaust every aspect of it There are other hon Members

Shri Khushwaqt Rai: I am not exhausting; I know I am not a sugar expert; there are other Members in this House who know better than myself

Shri Raghunath Singh (Barmer) Then leave it for us

Shri Khushwaqt Rai. I am leaving now

अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और उस के बाद बैठ जाऊंगा। मैंने थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया था कि खन्डसारी की जो पैदावार थी वह घटी और उसके घटने के कारण यह हुआ कि आपने एक्साइज ड्यूटी लगाई। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खन्डसारी का जो कुछ भी उत्पादन हुआ उस पर बैन लगा कर आप ने और भी एक मुसीबत पैदा कर दी। आज के दिन खन्डसारी राजस्थान और सौराष्ट्र में नहीं जा सकती। राजस्थान और सौराष्ट्र ही खन्डसारी के खाने वाले प्रदेश थे। जब आपने एक्सफैक्टरी प्राईस को कन्ट्रोल किया तो सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश और नार्थ बिहार में किया। इस सारे समय में जो और मिल थीं उन को पूरी छूट रही कि वह जितने दाम में चाहें उसे बेचें। मेरे पास इस बात का सबूत है कि किस तरह से शुगर दक्षिण में बेची गई, उस की चोर बाजारी की गई और कितनी कितनी ऊंची कीमत पर बेची गई। इसका कारण यही था कि आपने जो शुगर की एक्स फैक्ट्री प्राइस कंट्रोल की वह सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश और नार्थ बिहार में की। इन सब बातों के कारण दक्षिण में शुगर की चोर बाजारी हुई।

इन बातों से मुझे चिन्ता है और मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्री जी को भी चिन्ता होगी तथा ऐसा कुछ उपाय होगा कि आगे चल कर ऐसी कोई बात न हो सके।

Mr. Speaker: Motion moved:

> "That this House expresses its concern at the policy of the Government in regard to the distribution of sugar and urges upon the Government to take suitable steps to check the rise in the prices of sugar and profiteering by sugar interests"

I have received notice of some amendments Is Shri Saksena moving his amendment?

Shri S. L Saksena (Maharajganj) I beg to move

That at the end of the motion, the following be added, namely.—

> "and recommends that a High Power Commission of Enquiry, consisting of either a Supreme Court Judge or an eminent publicman be appointed to investigate into the complaint, and to find out the causes of the present sugar racket which has already resulted in the exploitation of sugar consumers to the extent of Rs. 16 crores during the last five months

and the evasion of income-tax on the profits so accruing to the sugar mill-owners".

Mr. Speaker: Shri Braj Raj Singh has tabled an amendment No. 2 There is no objection to part (a) of the amendment. But part (b) of the amendment "that sugar industry be nationalised" does not arise out of this and therefore, it is ruled out of order. He will be allowed to move the first part. I will treat it as moved. What I propose doing is this I will treat these amendments which are not out of order as moved if the hon Members are in their seats. Now, Shri D. R Chavan is here and he has tabled an amendment. Part (b) of his amendment does not arise out of this motion and so it is ruled out I will treat the first part of his amendment as moved. Shri Raghunath Singh has also tabled an amendment, No. 4 Copies of that amendment have been circulated.

Shri Braj Raj Singh: You may have to waive the time-limit of 24 hours; it has just been circulated.

Mr. Speaker: There is no harm, it is only a substitute motion

An Hon. Member: It seems that it is a Government amendment

Shri Raghunath Singh: No, Sir, it is my amendment

Mr. Speaker: Any hon Member who belongs to the Government party will certainly support the Government with such modifications as the occasion may require I shall treat that amendment also as moved. Now, how much time would the hon Members require? The time originally allotted was 2 hours and it has been increased to 2½ hours.

Shri Braj Raj Singh: I would request to extend the time by one more hour; this is a very important matter

Mr. Speaker: I have no objection if the hon. Members assure me of quorum. The private Members' business is to start at 2·30. Instead we may start at 3·30; then we may have to sit till 6. Is the House agreeable to this?

Some Hon. Members: Yes.

Mr. Speaker: All right. This will end at 3·30. A number of hon. Members want to participate I would like to make the time distributed among the various groups and give opportunity to all hon. Members. So, they will confine their remarks to 15 minutes Now, Shri Braj Raj Singh, I will then call Shri Shibban Lal Saksena and then Shri Raghunath Singh (*Interruptions*).

An Hon Member: There will be no quorum

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I am one of the Movers

Mr Speaker: I will call him also.

Shri Vajpayee (Balrampur): My name may be included

Mr. Speaker: Yes, I will call Shri Vajpayee also (*Interruptions*) Time permitting, I will allow all hon. Members.

Some Hon. Members: Please make it ten minutes so that others may get a chance

Mr. Speaker: I have allowed 15 minutes to Shri Braj Raj Singh. For others, only ten minutes.

Shri S. L. Saksena: For me also, 15 minutes

Mr. Speaker: Shri Saksena has fasted on this question; therefore, I will allow him 15 minutes. Other hon. Members will try to confine their remarks to ten minutes.

Shri Braj Raj Singh: I beg to move:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

"and recommends—

(a) that Government do appoint a Committee consisting of a High Court Judge and two members of Parliament one from each House to enquire into the undue profits earned by the sugar interests during the last few months"

Shri D R. Chavan (Karad) I beg to move·

That at the end of the motion, the following be added, namely.

"and recommends—

(a) that a Committee consisting of five members of Parliament, three from Lok Sabha and two from Rajya Sabha, presided over by a Judge of High Court, be appointed to investigate and enquire into unduly high profits earned by the sugar industrialists during the last few years"

Shri Raghunath Singh· I beg to move

That for the original motion, the following be substituted, namely

"This House expresses its concern at the rise in the sugar prices and after taking note of the steps already taken by Government recommends that Government should take such further steps as are found necessary from time to time to check the rise in the prices of sugar and profiteering by sugar interests"

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, ६ मई को इस सदन जवन एक कालिंग अटेंशन नोटिस की चर्चा हो रही थी तो मैंने आप के सम्मुख यह कहा था

"I fear that within the next three months when Parliament will not be in session, there will be a sugar famine in India...."

इसके बाद मैं कुछ और कहना चाहता था कि हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान के चीनी मिल मालिकों से मिली हुई है, उसकी उन के साथ साजिश है, जिसके कारण चीनी का अकाल पडेगा । इस के आगे मैं कुछ शब्द और भी कहना चाहता था जिन को कहने से आपने मुझे रोक दिया था । वे शब्द मैं नहीं कह सका था । मैं क्यों कहना चाहता था कि अगले तीन महीनों म हिन्दुस्तान के अन्दर चीनी का अकाल पडने वाला है ? कोई ऐसी बात नही थी कि मैं भविष्यवाणी करना चाहता था कोई भविष्य वक्ता हो गया था और इस बात को कहना चाहता था । लेकिन मैं जानता था, जिस तरह की प्रक्रियायें खाद्य मन्त्रालय में चल रहीं थी और जिस तरह से उन की साठ गाठ मिल ओनर्स से चल रहीं थी उनसे म फ पता चलता था कि जिस वक्त पार्लियामेंट नही बैठ रही होगी, उस वक्त ये लोग मिल जुल कर खूब धन्धा करेंगे । देश की जनता का ठगेंगे और उपभोक्ता को ठगेंगे । इस के लिये मेरे पास उससे पहले का उदाहरण मौजूद था आप को याद होगा कि सन् १९५८ मे जब पार्लियामेंट नही बैठ रही थी, उस वक्त खाद्य मंत्रालय ने एक आर्डिनेन्स पास किया उसमे कहा था कि सरकार शुगर को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है फारेन एक्सचेंज पैदा करने के लिये । इस के लिये आर्डिनेन्स जारी किया गया था । आर्डिनेन्स जारी करने के बाद १३ अगस्त को, ११ अगस्त से पार्लियामेंट बैठी, लेकिन १३ अगस्त को पार्लियामेंट में मंत्री महोदय ने कहा था कि अब तक हम एक पाई की चीनी भी बाहर नही भेज सके है और कोई फारेन एक्सचेंज हमे नहीं मिल सका है । इससे मैंने अन्दाज लगाया है कि हिन्दुस्तान का खाद्य मंत्रालय जो शुगर के पूंजीपति है उनके साथ साठ गाठ कर रहा है और हिन्दुस्तान की जनता को लूटना चाहता है, वह भी उस वक्त जब कि सदन बैठा

न हो, जब कि देश के प्रतिनिधि यहां बैठे न हों और उन से कोई जांच पड़ताल न कर सकें । लेकिन मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपकी उस व्यवस्था की तरफ जो कि आपने उस दिन की चर्चा के बाद दी थी । आपने कहा था :

"Whenever there is an abnormal rise in prices, I expect the hon. Minister of Food to come before Parliament without waiting for questions to be put and explain what has happened when the House is in session. But when the House is not in session, he should issue statements as to why this has occurred and what steps Government are taking. Notwithstanding everything done by the Government, it will remove a lot of misunderstanding about the actions of Government."

यह सब होते हुए भी इन पौने तीन महीनों में जबकि पार्लियामेंट नही बैठी थी लाखों इस चीनी टेंडर सिस्टम से जारी की गई और उस टेंडर सिस्टम को न तो अखबारों में प्रकाशित किया गया न लोगों को बतलाया गया कि किस तरह से टेंडर दिये जायेंगे । जो खाद्य मंत्रालय का नोटिस बोर्ड है उस पर भी नही लिखा गया कि कब टेंडर दिये जायेंगे और किस तरह से दिये जायेंगे । इस तरह की कोई बात नही की गई । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अध्यक्ष महोदय का डाइरेक्शन था, उनकी यह व्यवस्था थी कि जब कीमत बढ़ने लगे तो कीमतो के बढने के कारणों पर इस सदन म प्रकाश डाला जाना चाहिये और अगर सदन न बैठा हो तो हिन्दुस्तान की जनता को हिन्दुस्तान के अखबारो के जरिये और प्रेस विज्ञप्तियो के जरिये बता देना चाहिये कि क्या हो रहा है । लेकिन इस सम्बन्ध मे खाद्य मंत्रालय कतई चुप बैठा रहा, कही कुछ किया नही गया । इस बार जो टेंडर सिस्टम लागू किया गया, उससे पहले भी टेंडर सिस्टम लागू किया गया था । आप को मालूम होगा कि इससे पहले भी संकट पड़ चुके है चीनी के सम्बन्ध में और इसीलिये उन संकटों की देखते हुए मैंने इस संशोधन में यह व्यवस्था की थी कि अब चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । इस के अलावा अब कोई चारा नहीं रह गया है अगर हिन्दुस्तान की सरकार यहां की जनता को चीनी खिलाना चाहती है, अगर वह उन लोगों के साथ न्याय करना चाहती है जिन के वोटों पर चुन कर वह यहां आई है । परन्तु आज का यह विषय नहीं है और इस में वह नही आ सकता है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा अब इस के अलावा कोई चारा नही रह गया है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । तो चीनी में टेंडर सिस्टम पहले भी लागू हुआ था । जिन दोनों श्री रफी अहमद किदवई खाद्य मन्त्री थे, यह टेंडर सिस्टम लागू हुआ था । उन्होने नियम बनाया था कि जो व्यक्ति टेंडर पायेंगे वे ऐसे लोग होंगे जो पिछले तीन साल तक चीनी की तिजारत में रहे हों, जो इनकम टैक्स अदा करते रहे है । लेकिन हमारे वर्तमान खाद्य मन्त्री के राज्य में क्या होता है ? कोई नियम नही है कि कौन टेंडर पायेगा । कोई किसी तरह की खोज नही की जाती कि किसी ने चीनी का व्यापार किया है या नही, इनकम टैक्स दिया है या नही । यदि कोई पान बेचने वाला चाहे —मैं उस की तरफ कोई हिकारत की नजर से नही देखता, वह भी अपनी जगह पर अच्छा होता है, लेकिन तिजारत के मामले में ऐसा नही होना चाहिये तो पान बेचने वाले को भी टेंडर मिल जाता है । अगर वह कोई जनता का आदमी होता तो भी मुझे कोई ऐतराज न होता, लेकिन साजिश थी जो खाद्य मत्रालय मे ठग बैठे हुए है उन की, और मैं निवेदन करूंगा कि मुझे तो लगता है कि खाद्य मंत्री का भी कुछ हाथ रहा होगा ।

12.50 hrs.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

खाद्य मंत्री महोदय लगातार बैठे रहे और यह धांधलिया चलती रहीं और करोड़ों

[श्री ब्रजराज सिंह]

रुपयों का वारा न्यारा चलता रहा । जैसे कि मेरे मित्र श्री खुशवक्तराय ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि इसमें तो करीब ५०, ६० करोड़ का वारा न्यारा हुआ है और स्कैंडिल हुआ है । यह बड़े ताज्जुब का विषय है कि शुगर के मामले में ५०–६० करोड़ का वारा न्यारा हो जाय और खाद्य मंत्री चुपचाप बैठे रहें और उसके बारे में कुछ न कहें । टेंडर सिस्टम लागू हो और उस के कोई नियम न हों यह बड़ी गम्भीर घटना है । जिस पर कि इस देश की जनता और इस सदन को बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । जैसी परिस्थिति है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है कि श्री अजित प्रसाद जैन अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिये खाद्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दें । । अगर वे स्वयं इस्तीफा देने को तैयार न हों तो मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार को इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि आखिर इस तरह का स्कैंडिल एक बहुत गम्भीर घटना है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मैं आनरेबुल मेम्बर से पूछना चाहता हूं कि वह मेरे खिलाफ अगर कोई अभियोग लगाना चाहते हैं तो उसको साफ तौर से लगायें, खुल्लमखुल्ला लगायें और उसकी कुछ तफसील दें ।

श्री ब्रजराज सिंह : अभियोग तो बिल्कुल साफ है । मैं इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत तौर पर नहीं जाना चाहता लेकिन क्या यह खाद्य मंत्री महोदय की जिम्मेदारी नहीं है कि जब इस तरह का गोलमाल और स्कैंडिल चल रहा हो तो वह उसके बारे में कोई उचित और आवश्यक कदम उठायें और उसको रोकें ? शुगर मैगनेट्स द्वारा और स्वयं उनके खाद्य मंत्रालय के सम्बन्धित अधिकारीगण नाजायज तौर पर मुनाफा कमाये जा रहे हैं और इस तरह की अंधेरगर्दी के बावजूद वह चुप बैठे रहते हैं । मैं तो यह मानता हूं कि इस तमाम गड़बड़ी की सामूहिक जिम्मेदारी खाद्य मंत्री पर आती है ।

श्री अ० प्र० जैन : । इसका जवाब मैं दूंगा कि मैंने क्या क्या कदम उठाए ?

श्री ब्रजराज सिंह : वह जवाब देने का आपका अधिकार है बाकी यह सदन देखेगा कि आया वह कदम दरअसल उचित थे और ऐसे थे कि जिनसे यह अंधेरगर्दी और गड़बड़ी रोकी जा सकती थी कि नहीं । लेकिन जहां तक कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का ताल्लुक है उन के लिये तो चाहे कुछ भी क्यों न हो सरकार का अन्त में समर्थन करना जरूरी है और जब ऐसी हालत हो तो कोई खास नतीजा निकलने की कम ही आशा की जा सकती है ? बहरहाल अब मैं उस में नहीं जाऊंगा । लेकिन मैं तो यहां तक भी बता सकता हूं कि कुछ व्यक्ति हैं जिन को कि नाजायज तरीके से शक्कर दी गई है । अब चूंकि खाद्य मंत्री महोदय ने बीच में मुझे टोक कर यह कहा कि मैं साफ तौर पर उन पर इलजाम लगाऊं लेकिन मैं व्यक्ति विशेष को कोई महत्व नहीं देता चाहे वह अजित प्रसाद जैन हों या के० पी० जैन हों या कोई और साहब रहे हों । लेकिन मेरा तो कहना यह है कि मंत्री महोदय पर एक सामूहिक जिम्मेदारी आती है जिस से कि वे बच नहीं सकते. . .

श्री अ० प्र० जैन : मैं यह चाहता हूं कि इस किस्म की जो बातें कही जा रही हैं, तो वह केसेज बतलाये जायें कि कहां पर बेजा तौर पर दिया गया, गलत तौर पर दिया गया, स्पेसिफिक केसेज बतलाये जाय ताकि उन के ऊपर सख्त कार्यवाही की जा सके । इस तरह के वेग एलिगेशंस लगाना बिल्कुल नाजायज चीज है ।

श्री ब्रजराज सिंह : अब सदन ! माननीय सदस्य इस का कुछ न कुछ नतीजा र

निकालेंगे ही जो कि खाद्य मंत्री महोदय को बहुत बार बार टोकना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि यह खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह देखते कि टेंडर सिस्टम तो लागू कर दिया गया लेकिन उस के वास्ते कोई नियम नहीं बनाये गये और जिस को चाहा मनमाने तौर पर और पैसा ऐंठ कर चीनी दे दी गई। यह १, २ लाख टन का नहीं बल्कि सात लाख टन का मामला है और उस में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि फरवरी के महीने से ले कर अब जुलाई के महीने तक जब तक कि यह पार्लियामेंट नहीं बैठी थी तब तक हर टेंडर पर २००, ५०० और ७०० रुपये से ले कर ४ हजार रुपये तक का प्रीमियम पड़ा है। एक टेंडर में २२० बोरे चीनी दी जाती है फी टेन्डर १०० रुपये प्रीमियम के हिसाब से खाद्य मंत्रालय के चीनी के वितरण से सम्बन्धित अधिकारियों ने २००० तक प्रति टेन्डर के हिसाब से रुपये नाजायज तौर से कमा लिये। अब इस चीज के तो मेरे पास आंकड़े नहीं होंगे कि किस मौके पर और किस टेंडर में किस अधिकारी ने कितना मुनाफा कमाया लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस कमेटी या जिस कमीशन को बैठाने की मांग मैं ने अपने प्रस्ताव में की है यदि वह कमीशन बनाने के लिये खाद्य मंत्री महोदय तैयार हों और उस कमीशन के आगे मेरे चार्जेज साबित न हो पाएं तो मैं यह समझूंगा कि मंत्री महोदय के मुंह से इस तरह टोकने के कोई मायने थे। मैं चाहता हूं कि सरकार एक कमीशन हाई कोर्ट जज की सदारत में जिस में कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य हों बिठाने को राजी हो जाये और वह इस बात का पता लगाये कि किस तरीके से इस शुगर के मामले में करोड़ों रुपये का वारा न्यारा हुआ है और टेंडर सिस्टम में क्या खराबी थी।

२३-५-५९ को इस साल १ लाख ५० हजार टन चीनी बेचने के लिये छोड़ी जाती है जब कि सन् १९५८ में २ लाख ६६ हजार टन चीनी छोड़ी गई थी।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रोडेक्शन कम होने के कोई मायने होते हैं? आखिर कितना प्रोडेक्शन कम हुआ। ७२, ७३ हजार टन से ज्यादा तो कम नहीं हुआ है अर्थात इतनी चीनी कम पैदा हुई है। अब हमारे देश में विशेष रूप से मई का महीना ऐसा होता है जब गरमी भी पड़ती है और शादी ब्याह भी काफी होते हैं और चीनी का खर्चा आम तौर पर ज्यादा बढ़ जाया करता है।

श्री अ० प्र० जैन मैं आनरेबुल मेम्बर को बतला दूं कि मई के महीने में हम ने १ लाख ५० हजार टन चीनी फ्री सेल के लिये रिलीज की और ६० हजार टन टेंडर एलाटमेंट के लिये छोड़ी।

श्री बजराज सिंह १० अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर एलाटमेंट ४० हजार का नहीं थी कि ३८ हजार टन का है और १ लाख ५० हजार टन फ्री सेल के लिये रिलीज की गई। इस तरह यह कह सकते हैं कि कुल १ लाख ८८ हजार टन शुगर रिलीज की गई। पिछले साल २ लाख ६६ हजार टन चीनी रिलीज की गई। अब यह याद रखने की बात है कि ९ मई को यहां पर खाद्य मंत्री महोदय मानते हैं कि चीनी की स्थिति गड़बड़ होती जा रही है और सदन के सदस्य यह जानते हैं कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और स्पीकर महोदय सदन की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाये लेकिन इस के बावजूद हम देखते हैं कि ९ मई को पार्लियामेंट उठ जाती है और २३ मई १९५९ को यह १ लाख ५० हजार टन चीनी सेल के लिये रिलीज कर दी गई। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस साल पिछले साल के मुकाबिले इतनी कम चीनी क्यों रिलीज की गई? पिछले साल २ लाख ६६ हजार टन थी

[श्री ब्रजराज सिंह]

६८ हजार टन चीनी रिलीज की गई । मेरे पास इस समय वह आंकड़े नहीं हैं कि कितनी शुगर फ्री सेल के वास्ते दी गई और कितनी टेंडर एलौटमेंट के वास्ते रिलीज की गई ?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि पहले से ७२, ७३ हजार टन चीनी का उत्पादन कम हुआ लेकिन इस के बावजूद भी यह बात निश्चित है कि मुल्क में चीनी का काफी स्टाक है और इस बारे में मुल्क को बड़े मुगालते में रक्खा जाता है क्योंकि अगर हिसाब लगा कर देखा जाये तो मालूम पड़ेगा कि करीब २८ लाख टन चीनी का इस सीजन के लिये हमारे पास स्टाक है और इतना पर्याप्त मात्रा में चीनी का स्टाक रहते हुए भी कोई इस तरीके की आवश्यकता नहीं थी कि किसी तरह मुल्क में चीनी का संकट पैदा होता । लेकिन यह चीनी की मुल्क में कमी इस उद्देश्य से बताई जाती है ताकि चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर के फारेन एक्सचेंज कमाया जा सके । पिछले साल जो फोरेन एक्सचेंज पैदा किया गया वह ढाई करोड़ का था लेकिन खाद्य मंत्रालय बतलाये कि इस साल जो चीनी से उन्होंने फारेन एक्सचेंज कमाया वह क्या ३५ लाख से ज्यादा है ? कुल साढ़े सात हजार टन चीनी बाहर भेजी गई है, बात आप करते हैं १ लाख टन चीनी बाहर भेजने की लेकिन हकीकत में बाहर साढ़े ७ हजार टन ही भेजी जाती है । आप के यहां पर इस फारेन एक्सचेंज कमाने के नाम पर जो कि मैं भी मानता हूं एक अच्छा उद्देश्य है लेकिन वास्तव में होता यह है कि उस की आड़ में मिल मालिकों से साठ गांठ कर के नाजायज तरीके से मुनाफा कमाया गया है । मिल मालिकों ने भी मुनाफा कमाया और खाद्य मंत्रालय के सम्बन्धित अधिकारियों ने भी मुनाफा कमाया । अब खाद्य मंत्री महोदय भी कहेंगे कि आप के पास इस के लिये क्या कोई प्रमाण है तो मेरा तो कहना है कि सबूत तो वह कमीशन इकट्ठे करेगा । लेकिन मेरा मोटा अन्दाजा है कि शुगर और वनस्पति के जो डायरेक्टर हैं, उन के अफसरान और कर्मचारियों ने कम से कम २५ लाख रुपया इन ६ महीनों के अन्दर रिश्वत की शक्ल में वसूल किया है, टेंडर आदि देने में वसूल किया है ।

18 hrs

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : इस २५ लाख रुपये के बारे में क्या माननीय सदस्य के पास कोई खास मिसाल है ?

श्री ब्रजराज सिंह : अब मिसाल पेश करने के वास्ते मेरे पास वक्त नहीं है अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप को मिसाल दे दूंगा । इस की जांच पड़ताल के लिये एक कमीशन बनाया जाय । मैं निवेदन यह कर रहा था कि जब वास्तव में मुल्क में कोई चीनी का संकट नहीं था तो क्यों इस किस्म का बनावटी संकट पैदा किया गया और यह दिखाया गया कि अब चूंकि संकट आ रहा है इसलिये चीनी के दाम बढ़ रहे हैं । इस तरह की बात पहले से क्यों नहीं कही । क्या आप को विश्वास था मिल मालिकों पर कि वह दाम नहीं बढ़ायेंगे और इसलिये आप चुप चाप बैठे रहे ? क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई ? जो सख्त कार्यवाही आप अब करना चाहते हैं वह उस वक्त क्यों नहीं की गई । आप ने पूरा स्टाक हाथ में ले लिया तो फिर टेंडर सिस्टम की बात चलती है । उस से क्या होने वाला है । आप राज्य सरकारों को चीनी देना चाहते हैं । आप पंजाब की सरकार को देना चाहते हैं । वह कहती है कि वह एक मन पर सात रुपये के हिसाब से मुनाफा करेगी । आप ने जो स्कीम बनायी है उस में १ रुपया प्रति मन का मुनाफा देने की बात है । बम्बई सरकार ने एक रुपया फी बोरी की योजना बनाई है । केन्द्र की सरकार और बम्बई की सरकार में मतभेद है, केन्द्र की सरकार

और पंजाब की सरकार में मतभेद है। क्या इस तरह से आप चीनी की समस्या को हल करना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं थी। जब कहा गया कि चीनी की कमी होने वाली है इस समय भी चीनी की कमी नहीं थी। अब भी चीनी की कमी नहीं है। मंत्री महोदय को स्व० रफी अहमद किदवई की तरह साहस के साथ कहना चाहिये था कि देश में चीनी की कमी नहीं है और अगर जरूरत होगी तो हम बाहर से मगायेंगे और मुल्क के लिये उस की व्यवस्था करेंगे। मैं जानता हूं कि वह यह दलील देंगे कि उस वक्त यह बात कही जा सकती थी क्योंकि हमारी फारेन एक्सचेंज की पोजीशन खराब नहीं थी लेकिन आज यह बात नहीं कही जा सकती। लेकिन बाहर से एक टन भी चीनी मंगाने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में चीनी मौजूद है जिस का वितरण वह कर सकते थे और उन को करना चाहिये था। आज भी चीनी ४५, ५०, ५५ और ६० रुपये मन मिल रही है पर ३६ रुपये मन पर नहीं मिलती। इस से प्रकट है कि चीनी की कोई कमी नहीं है। अगर इस महंगाई का कोई कारण है तो वह आप की अव्यवस्था है। आप मिल मालिकों को नाजायज मुनाफा देना चाहते हैं। आप का शुगर और वनस्पति का डायरेक्टर चाहता है कि किसी तरह से नाजायज मुनाफाखोरी कायम रहे और उपभोक्ताओं से जितना ज्यादा वसूल किया जा सकता है किया जाये।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि यह ३६ रुपये मन का भाव किस तरह निश्चित किया गया। कहा जाता है कि यह इकानामिक प्राइस है जो कि चीनी के मिल मालिकों को दी जानी चाहिये। लेकिन आर्थिक मूल्य का भी कोई हिसाब होता है। मैं यह साबित करने को तैयार हूं कि यह आर्थिक मूल्य नहीं है। इसी तरह से भी आर्थिक मूल्य ३० रुपये ६५ नये पैसे से ज्यादा नहीं होता। जो आपने १३ रुपये ३ आने मन का कर चीनी पर लगाया है उस को मिला कर भी यह भाव ३० रुपये ६५ नये पैसे से अधिक नहीं हो सकता। आपने पहले ही इस में ५ रुपये ज्यादा का भाव निश्चित कर दिया है। लेकिन आज चीनी ४०, ४५, ५०, ५५ और ६० रुपये के हिसाब से बिकती है और आप कानों पर हाथ रखे बैठे हैं और कुछ करना नहीं चाहते।

अब कहा जाता है कि हम यह वितरण का काम राज्य सरकारों को दे देंगे। यह काम पहले से क्यों नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि पिछले ६ महीनों में चीनी के मामले में बड़ा गम्भीर गोलमाल हुआ है और इस पर सरकार को बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। वैसे मेरा तो ख्याल है कि इस का और कोई इलाज नहीं हो सकता। इस उद्योग का तो राष्ट्रीयकरण ही होना चाहिये।

आपने एक कंट्रोल एरिया बनाया। आप ने उत्तर बिहार को कंट्रोल एरिया में रखा। लेकिन दक्षिण बिहार को उस में शामिल नहीं किया जहां साहू जैन और डालमिया की चार मिलें हैं। पंजाब की मिलों को कंट्रोल किया गया लेकिन दक्षिण भारत की पैरी एंड कं० को कंट्रोल में नहीं लिया गया। यह शायद इसलिये किया गया कि जिन एरियाज में कंट्रोल किया गया वह सरप्लस एरिया है। मैं कहता हूं कि समस्या को हल करने का यह कोई ठीक तरीका नहीं है। मंत्री जी किसी चीज पर तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि वह सब को एक नजर से न देखें। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत की मिलें मुनाफा करती रहीं। नार्थ इंडिया के मिल मालिकों ने सोचा कि हम भी मुनाफा क्यों न कमायें। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीनी के उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था की जाय। इस के लिये दलील यह

[श्री ब्रजराज सिंह]

दी जायगी कि हम मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि हम को ७२ करोड़ रुपया मुआवजा देना होगा अगर हम इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मिलें सैकड़ों करोड़ रुपया का मुनाफ़ा कर चुकी हैं, इन का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है । अब इन्हें कोई सुझाव भी देने का प्रश्न नहीं है । आवश्यकता हो तो विधान बदलवाइये परन्तु राष्ट्रीयकरण कीजिये ।

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप गन्ने के उत्पादकों को २ रुपया प्रति मन के हिसाब से गन्ने का मूल्य नहीं देंगे तब तक आप को मिलों के लिये पूरा गन्ना नहीं मिलेगा । इसलिये मैं निवेदन करुंगा कि यदि आप अगले सीजन में चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो अभी से उत्पादकों को यह सूचना दे दीजिये कि उन को गन्ने का दाम दो रुपये मन दिया जायेगा । इतना दाम देने पर भी चीनी का मूल्य ३६ रुपये मन से ज्यादा नहीं होगा और चीनी का उत्पादन भी काफी हो जायगा ।

अन्त में मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिये एक कमेटी बनाई जाय । यह कमेटी एक हाई कोर्ट जज की सदारत में बने जिस में लोक-सभा और राज्य सभा का एक एक सदस्य भी हो और यह तीन सदस्यों की कमेटी इस सारे मामले पर विचार करे और यह पता लगाये कि क्या गोलमाल हुआ है और यदि गोलमाल साबित होता है तो मैं आशा करूंगा श्री जैन महोदय से कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे ।

इस के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो खंडसारी उद्योग पर टैक्स लगाया है उस से वह दब सकता है । उस की वही हालत है जोकि मिल के कपड़े के मुकाबले खादी की है । जिस तरह से आप खादी को सहायता देते हैं इसी तरह से आप को खंडसारी को भी सहायता देनी चाहिये ताकि यह उद्योग जारी रह सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं ।

Shri S. L. Saksena: Mr. Chairman, Sir, my amendment reads like this:

That at the end of the motion, the following be added, namely:

> "and recommends that a High Power Commission of Enquiry, consisting of either a Supreme Court Judge or an eminent public-man be appointed to investigate into the complaint, and to find out the causes of the present sugar racket which has already resulted in the exploitation of sugar consumers to the extent of Rs. 16 crores during the last five months and the evasion of income-tax on the profits so accruing to the sugar mill-owners".

Sir, I am very unhappy as I stand here today. A close friend of mine is in charge of the Ministry, but I have to be very blunt in exposing this racket. I have sent him a book on this subject. I think he has perused it. I also think he realises how keenly I feel about it. After all that, he repeats in this White Paper that the basic cause of the rise in sugar prices is the drop in production. That is utter falsehood. There cannot be a greater falsehood than this, and I should like to prove it.

He himself says that the amount of sugar production this year was 19·2 lakh tons. Last year it was 19·78 lakh tons. But that was up to October.

Therefore the position is this. There are still the months of September and October to go by. The production of sugar in the corresponding months of last year was about 50,000 tons. So, the total production of sugar up to October will be the same as in the last year.

Shri A. P. Jain: In the total production, the production in October, should also be taken into account.

Shri S. L. Saksena: What is the actual production. I want to know it.

Shri A. P. Jain: 19.05 lakh tons About 15,000 tons are produced in the special season.

Shri S. L. Saksena: Then your figure of 20,000 tons is not correct For, you know the factories produced sugar up to 15th October In Uttar Pradesh they produced more than 1,000 tons. From the figures of last year, you will find that production went up to 15 lakh tons Anyhow, the figures can be checked with the Ministry Even then, there is a drop of production by about 0·78 lakh tons taking 19 20 lakh tons as the total production In other words, 15,000 tons is the amount of production by which the whole total is less, is that a sufficient drop to warrant a sugar racket? It has dropped, in fact, from 20 29 lakh tons to 19·75 lakh tons in the same order of 15,000 tons, roughly Was that not so last year? Is there no production now? Why should there be such a difference this year?

I shall tell you the reasons It is not the drop in production that is the reason The Minister himself has said that 19·20 lakh tons was the production for this year and according to him, 3·31 lakh tons was the carry-over from last month That means 22·51 lakh tons was the total quantity of sugar available in the country. When there were 22 lakh tons of sugar in the country, according to him, 21 lakh tons was the consumption There was already a surplus. That was about 1.51 lakh tons When there was a surplus, and he knew the surplus, why should there be this sugar racket? When you have got in your shops 22½ lakh tons in the whole country, and when you know that only 21 lakh tons are consumed, why should there be this racket? The reason is that the position was so manipulated or the releases were so manipulated that the prices shot up. That is the main reason for this difficult situation.

When there was an enquiry into the sugar situation in 1949, what was the finding of the Tariff Board? They said, and the Sugar Syndicate at that time, said that although there was more stock of sugar in the country than required It was managed in such a manner that the prices shot up. What was the result? There was an enquiry held by the Tariff Board It was presided over by a Judge, Shri Surendranath The result ultimately was that the Sugar Syndicate was dissolved Today, you are the man—I mean the Minister—who have ordered the releases from month to month. Today there is a racket as bad as the one of the last occasion Should not the Ministry be dissolved and should he not go out of the Ministry? If the Sugar Syndicate was guilty of fleecing the consumers to the extent of Rs 16 crores, why should not the Ministry be censured?

Sir, I lay a very serious charge, and it is a very serious charge to be brought here Therefore, without any whitewash, in order to prove that you are not guilty, you must appoint a Commission of Enquiry to find out what is the truth It is in your own interest that you must prove that it is not as a result of bungling that all this has happened. I lay a serious charge I say, that had the Ministry not bungled in the months of April, May, June and July, knowing that it was a season of marriages and they were hot months, and had released quotas of sugar just more than required, all this would not have happened Then it would not have resulted in these happenings

The Minister asked me to give instances, where black money was made Does he mean to say that the men who deal in them would come

out? If it was so, what will be the result? Now, I want to ask you one thing. The market rate for sugar was Rs. 1-8 per seer. Even today sugar is selling at Rs. 30 a maund in Punjab and in Pathankot. This is the figure ruling this morning. Today's quotation in the Times of India is Rs. 121-8-0 a bag in Kanpur. That is the wholesale price of sugar in Kanpur today. If Rs. 44 per maund is the rate of sugar today, you give a release of sugar by tender at Rs. 36 per maund. Rs. 8 is the margin. Do you think that the people in the Ministry are angels to give it without any consideration? When the sugar is released to people who have got the quotas, you will find that there are many people with the same name or firm who have got the sugar because they have greased the palm of the Ministry. I can give the names of the people if an enquiry is made, and lay it on the Table then, and I can tell you people with the same names and firms—not panwalahs—and even prostitutes have got quotas of sugar and they have sold them in the black market I have the names and if a Commission of Enquiry is appointed, I can give those names to the Minister This is not something which is secret. It is a thing that everybody knows in the Kanpur market, Delhi market, Hapur market. It is a serious scandal, and the public has been robbed of about Rs 16 crores, and if this thing continues, it will go still further

I can tell you the figures from your own statement The price of sugar in Kanpur market was Rs 42·55 Today it is Rs 44·55 I can tell you that if this thing continues, it will go up to Rs 50, Rs 60 or even Rs 70 by 1st September Where is the control price and where was it during the last five weeks? The quotas were given to the State Governments How does it happen that there is sugar even now in the market and is selling at the black market prices? Where does it come from? Last year you had not given quotas and you gave them only to the State Governments The reason for this situation is, as I have been saying earlier, the mills had been transferring their free stock to their own agents in the name of benami transactions and they are keeping this sugar. They are now selling at high prices. Once you do not release any free quotas, the result will be that in the month of December, only that sugar will sell which has been hoarded by the sugar millowners and given to the benami agents. That will sell at Rs. 80 to Rs. 100 per maund. You will see it in September or October if your control continues to be as it is, and it is absolutely ineffective.

Take the Kanpur market. I was there yesterday. You have given 1,475 tons of sugar for one month there. That means 14,000 bags. In the previous two or three months they have been selling 15,000 bags every month and about half of it went outside. 25,000 tons is the consumption of Kanpur city and Kanpur district as a whole But you have given only 50,000 bags. About 1,270 tons is the quota. They have not taken all the quota. They have taken about 16,000 bags. The result will be that there will be no sugar in the shops and in the market, and the black market will proper and the price of sugar will shoot up

Therefore, I say that you must be very careful in this matter It is not a thing which you can easily manipulate It is a thing which must be regulated and which must have normal channels I therefore recommend that if you have got sufficient sugar, more than what is required, then, your duty is to see that anybody can offer to purchase the sugar and let them get what they want. You should have done that. Ask the mill owners not to sell one single seer of sugar Let the entire sugar produced by the mills be taken over by the Government and the Government must sell it. When the mill-owners see that sugar is selling at Rs. 45 a maund, will they sacrifice so many rupees?

The Minister also has admitted that the sugar has been selling at Rs 8 to Rs 12. That means they have taken black money at the mill gate. I know the factories and I know the names of the mills In fact, the market quota-

tion went to show that Rs. 12 was the premium. Today, the prices range from Rs. 8 to Rs. 12, and these are the practices openly done. Yet, not a single action has been taken against any mill-owner. What is this? Your order is that more than one seer should not be consumed, and the statement says that there is a quota. Can you not prosecute the concerned people, and can you not prove that they are doing it? Everybody knows what is the price at which sugar is being sold.

Therefore, I charge you that you have not done your duty, you have not seen to it that the mill-owners do not indulge in such practices. I therefore demand that the mills should not be allowed to sell any sugar. Whatever they produce must be taken over by the Government and the Government must give to every trader from that stock You have got the system of licensing now It is very good You have got the system, and so, whatever the people demand, give them Then sugar will be sold at a cheaper rate and at a smaller cost At present, the sugar released through quotas sells at Rs 1 or Rs 1·02 That is much more than what the trader sells in normal times 15 annas was the price at which sugar was being sold about a year back

I have given the reasons why the present situation has come about What was the position last year? What is the difference between last year and this year? I say it is because of the change in the personnel—in the directorship in the Ministry When Shri Prasad was there, he gave quotas freely and gave tenders freely. In the months of July and August, the price fell below Rs 35 per maund But after the new Chief Director has come, there has been black-marketing and the price of sugar has risen. At the crucial moment, when people required more sugar, you hoarded it in the godowns in March and April. In April, we expected that there would be some more release of sugar, but it was not done. I have got the figures here. Last year, in the months of January, February, March, April, May and June, the quantity released was 8,82,000 or about 9 lakh tons. This year the quantity released was much less compared to last year. The release was about 2 lakhs tons less this year In the hot months, in the crucial months of May and June when sugar was badly needed if you had released enough sugar, the position would not have been so bad.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): The Chief Director was on leave from the end of last month How is it that when he was officiating, the allotments were made? The hon. Member was saying that after a change in the post of the Chief Director, there has been some abuse

Shri S. L. Saksena: When did the new Chief Director take over?

Shri A M. Thomas: He was there only from December last.

Shri S. L. Saksena: If you see the price of sugar in November, it was below Rs 36 After December, the prices began to rise and black money has been charged All the tenders were not freely accepted. If licences had been issued to proper sugar merchants, there would not have been this serious situation My charge is, after that you have been discriminating in accepting tenders and black money has been charged Although there was less sugar product on last year, the prices were not so high last year

The sugar manual gives the amount of sugar consumed every year. Khandsari sugar is also consumed. In 1956-57, 1 lakh tons was the consumption of khandsari The total sugar consumption was 20 8 lakhs tons. 19·83 lakhs tons was the consumption last year This year the consumption has increased In fact, as Shri Rai stated, the consumption of khandsari has gone up to 3 lakh tons If you take all these things into account, you will find that this serious situation is

[Shri S. L. Saksena]

not so much due to the actual consumption as to the fact that sugar is hoarded by the sugar mill agents; they are keeping it for being sold in black-markets, because your control is not properly functioning.

Another thing I was surprised to find was this. The main markets for khandsari are Rajasthan and Punjab. But he has stopped the movement of khandsari from the 27th July even to the markets. That sugar is not here in U P. Its main markets are Rajasthan and Punjab, but in Punjab sugar is selling at Rs 62 per maund. So, unless you allow this sugar to go there, you will consume your white sugar and there will be famine again

I now come to the sugarcane prices. You say, if you increase the price of sugarcane, the price of sugar will go up. But what has happened now? You have yourself said that sugar was selling at Rs 47 per maund and the price of sugarcane is still Re 1-7-0 Is it not most cruel that the sugarcane-grower should not get any part of it? If you had not had this control and if sugar been sold at the high price, you would have got income-tax Now because of your control, there is loss of income-tax So, I demand that there should be an enquiry to find out how much money has been charged in the black-market, which mills have made that black-market money, how much money has been lost by the Government by way of income-tax and if the money has been there, how much of it must go to the cane-grower and to the sugar labourers whose wages are so low

Therefore, my motion is a very simple and a very urgent one. So, appoint an enquiry commission where I will give all the evidence to prove that the mill-owners are guilty. I say the mill-owners have been mainly responsible for the propaganda of scarcity. There is no scarcity, because, as I told you, there is only a drop of 0·5 lakh tons in production and for that there is so much propaganda of scarcity. Go back to 1952-53 when production was 12 lakh tons and consumption was 16 lakh tons. Shri Kidwai was able to keep the prices at a low level even in that year and sugar was selling at Rs. 30 per maund all over the country. So, when there was real scarcity, there was plenty; now when there is plenty, you say there is scarcity. I, therefore, say that it is necessary that you must take a leaf out of that book and see how he did it.

My only message is this. We have got enough sugar, but this control will not do Let every tender which comes freely from the licence-holders be honoured and everybody will get enough sugar. They will take it to the smallest corners and there will be no black-marketing. But if you do what you are doing now, the result will be this Sugar is already in the black-market It is hidden in the hoarders' godowns and they will sell it at black-market prices

Shri Heda (Nizamabad). Mr Chairman, Sir, I think the country is facing a strage predicament The consumer is paying much more for sugar than I think he had at any time imagined that he would have to pay The producer had not got the price he wanted Last year, some of us who represent the sugarcane-growing areas had desired that Government may fix a higher price for sugarcane, but it was rejected on the plea that the consumer should not suffer If you increase the price of sugarcane, the price of sugar will increase and the consumer will have to suffer. Because of this argument, we reconciled ourselves.

If you look at the position today, the country has suffered in the sense that if we had given a higher price for sugarcane, the producer would have produced more sugarcane not only in terms of greater yield per acre, but also in terms of getting

more areas under the cultivation of sugarcane. Thus, all concerned—the consumer, the producer and the country—have suffered. The production of sugar is not much less to create this scare. In fact, I very well remember that the Food Minister did well by assuring the House time and again that the carry-over stocks are quite enough and they would be able to cope up with the increased demand of the consumers. Not only that; he struck a cheerful note and said that the export of sugar, as it was programmed, will be carried out. So, we thought there would be no difficulty, though it was expected that there would be less production of sugar. No doubt the production of sugar fell below the estimated quantity, but even then the production even today has not fallen to such an extent as to have created this scare.

Obviously, therefore, there is something wrong in handling. Take the case of releases is the months of March and April. The sugar release had been to the extent of 1,70,000 tons each month. It is expected that the consumption this year would be to the tune of 21 lakhs tons; *i.e.* 1,75,000 tons per month. Particularly in the hot months, when there is greater demand for sugar, the releases had been less; they should have been a little more. When an unreal scarcity propaganda was created, thereby resulting in the sugar prices rising, I do not think anything would have been lost if you released a little more sugar, as we are doing now, *viz.*, 1,90.000 tons per month. Had we released this much sugar in March and April, the situation would have been better. We would have hardly needed 1,85.000 tons or something like that. So, the handling of the situation, particularly in the realm of releases, was not accurate to cope up with the situation. Another thing in this regard is that when we made the releases we thought that the sugar in that quantum will reach the consumer. That does not necessarily happen every time. We know how the market goes and how the cycle of the trade works. From the factory sugar is released, but then it is held by the wholesalers and the wholesalers can play with the consumers freely. It is a common knowledge practically in every big city—we have seen it—they create an artificial scarcity, charge more prices and thereby get higher profits. That has happened and this is the reason.

Therefore, taking advantage of the laws that we have in force, had we gone into the details of the trade at various levels, particularly at the wholesale level, and the agency between the wholesale and retail trade, had we kept a good watch over it and penalised some persons, the effect would have been quite different. Even now I feel that what is needed is not an enquiry neither full-fledged rationing; what is needed is a good watch over the trade to see that they play the game very fairly. The Minister should employ certain agencies, some people, to go incognito and find out the rates at different places at different levels and if there are any malpractices strong and prompt action should be taken against the anti-national elements that are working in the field. A few actions here and there may bring down the situation to normalcy and the scarcity which is so much felt now all over the country would not be felt.

Now I come to the question of zones. Some zones have been created. Take the case of the South. I belong to the southern zone which consists of the four States of Andhra Pradesh, Mysore, Madras and Kerala. They were put in one zone thinking that they are self-sufficient, so far as sugar is concerned. Though we are deficit in sugar, our deficit is not very much. Particularly, if we look at the expansion programmes of my State I am sure that in the near future the Southern zone will not only be not deficit but also will be surplus. But what happened this year? When a

[Shri Heda]

separate zone was created sugar started being smuggled out of the zone, particularly to Bombay, and this resulted in greater scarcity in those areas. I do not know anything about U.P. but it has affected us, because no sugar was allowed to be imported to our zone and some sugar was going out of the zone. The result was that prices increased and no action was taken to stop them So, we in the south zone had a little more difficulties I hope Government will take cognizance of this fact and allow more sugar to be taken to the south zone so that the position there may improve

Again, I make the same plea that what is required in the situation is a better watch over the trade, particularly over the wholesalers and the middle links, which are many times unnecessary between the wholesaler and the retail trade As some hon Members have said, many of these middle agencies are not real agencies They are not in the field; they are just bogus ones In these matters favouritism in various spheres of life does play its own part. However, if we keep a good watch over this and penalise the elements that are not falling into line, who are chargeing more rates than prescribed by the Government, the situation can be controlled better, the prices will come and we will not be faced with any difficulty

With these few remarks I oppose the motion, as well as the amendment moved by Shri S L Saksena

Shri S. M. Banerjee: I rise to support the motion of my hon friend, Shri Khushwaqt Rai I remember when this question was raised in this House the hon. Minister assured us that every possible step was being taken to check the prices This unfortunate statement of the fortunate Minister is before us and I have read it with keen interest. And while reading I found that the Ministry or the Central Government knew about this crisis. It was in sight in the month of February, 1959. It is also stated here that they had this knowledge that the mill-owners and the trade will exploit the situation. When I read the statement I could not possibly understand the helplessness of the Ministry, whether at the Centre or at the States. Were they actually helpless or was it a deliberate collusion with those magnates who are trying to create a situation in the country in which it would be difficult for anyone to function? I accuse the hon. Minister and his Ministry, because I find that such a crisis, which was already in sight, could have been avoided.

It is also said here that different figures were shown and some figures were not shown in the books and it was in the knowledge of the Food Ministry that the mill-owners were adopting these tactics I want to know the action taken against these mill-owners This is not the first time they wanted to create this situation, this is not the first time they wanted to exploit the situation, because they are exploiters by nature, it is in their blood and they go on exploiting any situation whether it suits the Government or not

So, my contention is this The Food Ministry has utterly failed in its duty Today, I am sorry to say that if you analyse every letter—I have analysed it—you will find that in the word "sugar" "s" stands for "scandal" "u" for "unchecked", "g" for "glaring" "a" for "amazing" and "r" for "real" So, "sugar" is an "unchecked, glaring, amazing but real scandal". And I am really sorry to see that even today the Minister feels like remaining as a Minister Don't you think that it is high time that the hon. Minister resigns peacefully and gracefully? The entire situation has been created in such a way that the common man does not feel that this crisis could not be averted.

In 1949 when there was a sugar racket—it is quite evident from the book written by my hon. friend, Shri S. L. Saksena—the hon. Prime Minister said in this very House.

> "What is more disturbing is not the fact that some of us have got sugar and some of us have not been able to get sugar but the fact that sugar position should deteriorate so rapidly and the situation could not be checked quickly. That is a fact which is very important and we should find out who is particularly responsible for this and who is guilty of it."

Some reasons have been attributed. They say that the sugar production was low and the quality of the cane was not good. May I mention for the information of the hon. Minister that in this very House when we the Members wanted to discuss why the Central Government stands in the way of increasing the price of sugar, especially when both the Houses in U.P. and Bihar have unanimously recommended that the price of sugarcane be increased to Rs. 1·75 it was rejected on the ground that the prices will be increased.

Even the hon. Prime Minister, who took part in that debate held the same view So, I can tell you that these mill-owners and these magnates not only hit the consumer but equally hit the cane-growers and the workers. The Government today is a silent spectator of the whole show.

Now, I take the distribution of sugar. In U.P. they have started distribution of sugar at the rate of .97 nP per seer through the fair price shops and they feel that the crisis in Uttar Pradesh has been solved. I cannot blame the State Government for that particular state because their crisis is much more than the sugar crisis. They are unable to solve that. But I can tell you that only 40 per cent of the population is getting sugar through these shops. How can a man feel that Government is doing something? He knows that if he can wait patiently in the queue he can get one, one and a half or two seers of sugar, but if he has money in his pocket, he can go into the market and purchase any quantity at the rate of Rs. 1|4|- or Rs. 1:25.

13.41½ hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

So, the production has been deliberately decreased by those who wanted to have fabulous profits. Nobody can deny that the sugar magnates made fabulous profits during the last so many years. I will read out how the profits increased. If you take Base 1939 as 100, these are the index figures:—

1942	126.7
1943	157.8
1944	133 5
1945	108 9
1946	122·4

Then I am quoting from 1951 onwards.

1951	221
1952	409
1953	419
1954	336
1955	413
1956	454 5

How can anyone believe that there is no profit? So, my submission is that the sugar magnates with the help of the Food Ministry both at the Centre and at the State level have created this situation.

In 1949, I remember, when a committee was appointed to go through this, they made certain observations. They asked that action should be taken against the Sugar Syndicate. The recognition of the Sugar Syndicate was withdrawn but later on it was restored with a mild warning. It was in the knowledge of all these people that such a situation may arise

[Shri S. M. Banerjee]

in the future also. The Sugar Enquiry Committee, 1950, which looked into the popular complaints against the Sugar Syndicate, reported as under:—

> "The Sugar Commission started investigation into these complaints and addressed the Sugar Syndicate on various matter in connection with it, but the Syndicate followed a policy of delay and evasiveness which clearly showed that the Syndicate was reluctant to submit to the control and supervision of the Sugar Commission."

It is quite evident that right at the beginning, in 1949, the same thing happened and today the sugar situation is almost out of control. You produce more otherwise there is no solution. But the workers are suffering at the hands of these mill magnates. Cane-growers are also suffering. The consumer has been hit and today a situation has arisen that a high power commission should go into this scandalous affair. Till it submits its report, it is necessary that the hon. Food Minister may kindly resign.

An Hon. Member: He has not suffered.

Shri S. M. Banerjee: Whenever a question is asked, whether it is about foodgrains or about fodder, whether it is about sugar or about salt, some statistics are given in this House. I have received a telegram from Trivandrum which says that the price there is Rs. 47-8 per maund. It is from the Chamber of Commerce there which is patronised by them. They say that this rate is unprecedented for the past many years. My information is that the biggest manufacturers there are Parry and Company. They were supplying sugar at a lower rate but they were asked, "You cannot do it; now you have to give at a particular rate." I do not know why, when the mill-owners were ready to give at a lower rate, they were asked to increase the rate.

Shri A. P. Jain: Who asked them?

Shri S. M. Banerjee: I do not know. Somebody must have asked. But, today the rate is Rs. 47-8-0 per maund.

So, let a commission be appointed. Let a judge of the Supreme Court be appointed, though I know that after the submission of the report the report may not be accepted because even the recommendations of the Supreme Court judges are not accepted or are flouted by this particular Government. So, my submission is that immediate steps should be taken....

Mr. Deputy Speaker: This ought not to have been said that the decisions of a Supreme Court Judge are not respected by the Government.

Shri Vajpayee: This is what is happening.

Shri V. P. Nayar (Quilon): Even when the judge himself is considered....

Mr. Deputy-Speaker: No authority in the country can afford to flout the decision of the Supreme Court. This should not be said.

Shri S. M. Banerjee: I can use the mild word 'ignored'.

Mr. Deputy-Speaker: Not that. The Supreme Court has got wide powers to see that its decisions are implemented, executed and obeyed.

Shri V. P. Nayar: The decision on the report of Justice Vivian Bose is fresh in our memory.

Mr. Deputy-Speaker: That is not a decision of the Supreme Court. Commissions are different.

Shri S. M. Banerjee: Another thing is about distribution.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now. 10 minutes have been given to each hon. Member.

Shri S. M. Banerjee: I want only another minute and a half. I have come to distribution. Regarding distribution, it says:

> "From the May release, the Uttar Pradesh Government decided to arrange for distribution of sugar through the Uttar Pradesh Co-operatives Federation...."

What is this Uttar Pradesh Co-operatives Federation? I have no time, otherwise I would have traced the history of those who have formed this Federation. They are the same men, the same exploiters but in a different form. The Sugar Merchants' Association in Kanpur itself issued a press statement, went to the District Magistrate and met the Food Ministers, both at the Centre and in the State. They say, "We promised to distribute sugar at a reasonable price of ·95 nP." They were not considered. They said, "No, we have got this Co-operatives Federation" because, I know that they are the offshoots, the branches of those mill-owners who have created this situation.

So, what I submit is that this commission should be appointed at the earliest. Till that time there should be proper check and this hoarding must stop. Uneven distribution of sugar must stop. There is a serious situation in the country and I again respectfully submit to my hon. friend, the Minister, whom I respect most, kindly to submit his resignation in the larger interests of the country because in that case the people will feel that the hon. Minister has taken it very seriously.

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी के व्यापार और उस के वितरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया। अभी ही नहीं कहा गया है, बहुत वर्षों से कहा जा रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि वह मसला वैसा ही है कि आप कुत्ते की दुम को सीधा कर दीजिये पर वह फिर टेढ़ी हो जाती है। जिस मसले के ऊपर विचार किया जाता है, वह तो सुधरता नहीं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। दोष किस का है यह भी मालूम तो हो ही जाता है परन्तु कोई अपने दोष को मंजूर करने के लिये तैयार नहीं।

बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन एक तो समय उतना नहीं है दूसरे मेरा स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं है कि मैं उतनी बातें कह सकूं। मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। हमारे भाई सुवावक्त राय जी ने कहा कि जब हमारे भाई अजित प्रसाद जी जैन उन की बगल में बैठा करते थे तो वह कहा करते थे कि गवर्नमेंट कमेटिया वगैरह तो बनाती है लेकिन असली सवाल को माल्व नहीं करती। उन्हों ने उस समय कहा था कि कंज्यूमर से शुगर इंडस्ट्री ने आठ करोड रुपया ले लिया और पता नहीं चला कि वह कहा चला गया। उन्हों ने यह भी कहा कि जब से वह आये हैं तब से कमेटिया वगैरह भी नहीं होती हैं और वह कहते हैं कि १७ करोड रुपया ग़ायब हो गया। मुझे नहीं पता कि कितने करोड़ रुपया ग़ायब हो गया है। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। परन्तु उन्हो ने जो बात कही, वह यदि सच है, तो मैं खाद्य मंत्री महोदय से कहूगा कि वह तलाश करें कि वह १७ करोड़ रुपया कहा गया है। यह बहुत जरूरी है। बहुत से भारी-भारी आरोप खाद्य मंत्री पर लगाये गये है।

Shri Goray (Poona): He has survived all that.

श्री झुनझुनवाला : वे आरोप हमारी समझ में ठीक नहीं है। खाद्य मंत्री जी से यह भी कहा गया है और बार-बार कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिये। मेरा सुझाव खाद्य मंत्री जी से यह है कि वह इस्तीफा कभी भी न दे। जो आरोप उन पर लगाये गये हैं, कांग्रेस के एक सच्चे मिनिस्टर की हैसियत से उन सब आरोपों

[श्री झुनझुनवाला]

का वह सामना करें और कमिशन के द्वारा और किसी भी तरह से पब्लिक को दिखला दें कि ये आरोप झूठे हैं ।

एक माननीय सदस्य वह एपायट करेंगे ।

श्री झुनझुनवाला वह एपायट करेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कहता । इतनी देर में इस बारे में राय देना मुश्किल है, क्योंकि उस के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही जाती हैं । लोग पांच दस मिनट में इतने गैर-जिम्मेदार तरीके से इतनी बात कह डालते हैं, जिन से कोई नतीजा नहीं निकलता है । बनर्जी साहब कह बैठे कि शूगर इंडस्ट्री में वर्कर्ज को मारा जाता है, कन्ज्यूमर्ज को मारा जाता है, इस को मारा जाता है, उस को मारा जाता है । उन्होंने यह नहीं कहा कि जिलाया किस को जाता है । वह यह भी कह गये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी यहां पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हों ने अपनी गलती महसूस की । बनर्जी साहब ने जो बातें कहीं, मैं नहीं कहता कि वे गलत हैं, मिथ्या हैं ।

श्री स० एम० बनर्जी : तजुर्बा कम है ।

श्री झुनझुनवाला : तजुर्बा तो सब से बेशी है । वह कानपुर में रहते हैं और काम करने आये हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात कही जाये, अगर आंकड़ों से उस का समर्थन हो, तो उस का मूल्य होता है, नहीं तो सदन के उन लोगों पर, जो कुछ जानते नहीं हैं, बूझते नहीं हैं, कुछ विशेष पढ़ते नहीं हैं, एक अजीब तरह की छाप पड़ जाती है कि क्या है, क्या नहीं है । वे उलझन में पड़ जाते हैं ।

सवाल इस समय यह है कि शक्कर के दाम कब से बढ़े । मैं बाहर नहीं जाऊंगा । हमारे खाद्य मंत्री जी की जो रिपोर्ट है, उसी पर दो चार बातें कह कर बैठ जाऊंगा । उन्हों ने कहा कि मिल-मालिकों को फरवरी मार्च में पता चल गया था कि प्रोडक्शन कम होगा, इसलिये वे लोग इस का खूब फायदा उठाने लगे । उन का यह केस नहीं है कि फरवरी मार्च में दाम बढ़े । उन्हों ने यह भी नहीं कहा कि उन को मालूम था या नहीं कि फरवरी मार्च में उन को पता चल गया कि प्रोडक्शन कम होगा । हम को पता चला है कि उन को बार-बार चिट्ठियां लिखी गईं फरवरी मार्च में कि इस साल प्रोडक्शन कम होने वाला है और यह कारण है, जिस से प्रोडक्शन कम होगा और अगर प्रोडक्शन कम होगा, तो स्वभावत चीनी के दाम ऊंचे जा सकते हैं । हम को यह खबर मिली है । वह चुपचाप बैठे रहे । उन्हों ने कोई हां न कुछ भी नहीं कहा । जब ९ मई को कालिंग एटेंशन नोटिस दिया गया, उस समय भी जवाब यही मिला कि नहीं, चीनी हमारे पास इतनी है कि दाम ऊंचे जाने का कोई भी डर नहीं है ।

श्री शुभवक्त राय यह कहा था कि साल भर का काम चल जायगा ।

श्री झुनझुनवाला यदि उन्हों ने यह कहा कि साल भर का काम चल जायेगा, तो यह सही बात थी और हमारे फूड मिनिस्टर और फूड मिनिस्ट्री यदि सावधान रहती, तो साल भर का काम चल जाता और कोई कमी-बेशी न होती । मैं यह नहीं कहता कि इंडस्ट्री और ट्रेड एक दम से पाक है । मैं नहीं जानता । मैं ने फिगर्ज भी नहीं देखीं । मैं उन्हों की बात बतलाता हूं । लेकिन कहीं पर तो यह गलती हुई है । माननीय सदस्य ही विचार करें । मैं फूड मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं । मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट में यह बात ठीक है कि मई के पहले हफ्ते तक सब दाम एक दम से ठीक थे । उन में कोई भी ऊंच-नीच का सवाल नहीं था । यद्यपि श्री शुभवक्त राय ने बताया है कि नहीं, फरवरी मार्च में दाम एक, सवा रुपये बढ़ गये थे,

लेकिन इस के बारे में उन्हों ने आंकड़े नहीं दिये। यदि दिये होते, तो मेरे पास आंकड़े होते, मैं उन से कम्पेयर कर लेता और शायद कुछ कहता। बिना आंकड़ों के कोई स्टेटमेंट करने से कोई लाभ नहीं है। उस के बाद उन्हों ने यह बात भी साफ़ कर दी--

"The Food Minister has made it clear that from the July release, the entire production has been taken over by the Government in the controlled area for direct allotment. In effect, therefore, if there was any exploitation by the factories or if they have charged higher prices as alleged, this was restricted to only two releases made by the Government, one towards the end of May and the other towards the end of June. In these releases, the total quantity released was 375,000 tons"

इस आंकड़े की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ३७५,००० टन उन्हों ने जो रिलीजिज में रिलीज किये थे। इस में से केवल १,१९,५६२ टन कंट्रोल्ड फ़ैक्टरी से रिलीज कराई गई और बाकी रिलीज हुई फूड मिनिस्ट्री के परमिट से या कोटा से--उस को क्या कहते हैं?--जिस के बारे में यहां तक हुआ कि फूड मिनिस्ट्री में लाठी-चार्ज हुआ।

श्री शि० ला० सक्सेना : टेंडर कहते हैं।

श्री झुनझुनवाला : शायद टेंडर कहते हैं। मैं नहीं जानता।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी कहते हैं। वे समझ गये। अब माननीय सदस्य आगे चलें।

श्री झुनझुनवाला : उपाध्यक्ष महोदय, वे समझे नहीं हैं। बिना समझे वह कहने लगते हैं कि तुम गलती करते हो।

14·00 hrs.

२,५५,४३८ में से कुछ तो परमिट, टेंडर के जरिये मिला। कुछ उन की फ़ैक्टरियां थीं--कारण उन्हों ने नहीं बताया है--साहू-जैन की बिहार में फ़ैक्टरी थी, साउथ इंडिया में सभी फ़ैक्टरियां थीं। कुछ वहां से रिलीज हुआ था और कुछ रिलीज परमिट, टेंडर, से किया गया था। तो इस में से यह आंकड़े याद रखिये कि ३२ पर सेन्ट जो रिलीज था वह तो था कंट्रोल्ड फैक्टरीज से, जिन के ऊपर सारा दोष हमारे फूड मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में लगाया है और ६८ पर सेन्ट जो था वह उन दो जगहों से आया था। कुछ तो उन की पेट फैक्ट्रियां थीं जिन के ऊपर उन्हों ने कंट्रोल नहीं किया था, दूसरी चीज यह थी कि जिन-जिन को चाहते थे उन को परमिट देते थे। वहां से यह चीज आई। जब करीब ६८ पर सेन्ट इस तरह की चीजें उन के हाथ में थीं तो मेरी बुद्धि तो नहीं कहती है कि ६८ पर सेन्ट जो चीनी थी वह सब चीज को कंट्रोल करती थी, ३२ परसेन्ट वाले नहीं कर सकते थे। तो यदि कोई अन्याय हुआ है तो वह ६८ पर सेन्ट वालों की तरफ से हुआ है, ३२ परसेन्ट वालों की तरफ से नहीं हुआ। हां यह जरूर है कि इस के साथ यह बात भी हुई कि आखिर ३२ पर सेन्ट वाले भी पीछे क्यों रहते। अगर उन को ज्यादा मिलेगा तो वह उसे लेंगे ही। मैं फूड मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि आखिर यह क्या बात है कि आप के ऊपर इतने चार्जेज लगाये गये हैं परमिट आदि के बारे में और आप दोष दे देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स के ऊपर। जैसा मैं ने कहा कि वह कोई पूरी तरह से साफ़ नहीं है, लेकिन आप को कम से कम इम्पार्शल तरीके से सब कुछ संसद् के सामने रख देने चाहिये जिस से संसद् विचार कर सके कि क्या बात है। अगर आप संसद् के लोगों को अंधेरे में रखकर तरह तरह की बातें

[श्री झुनझुनवाला]

करने लगेंगे तब तो कोई शुगर प्राब्लेम हल होने वाली है नहीं । आज सरकार कहती है कि हम कंट्रोल कर के सब चीजों का ठीक तरह से वितरण कर सकते हैं, लेकिन अगर उन का इसी प्रकार का तरीका रहा और यदि इसी तरह से मिसलीडिंग स्टेटमेंट लोगों के सामने आते रहे तो मैं नहीं समझता कि जो सवाल आप के सामने है उसे आप किस तरह से हल कर सकते हैं । केवल इस तरह के मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे कर अगर हमारा समय निकाल देना चाहते हैं तो ठीक है, वह तो निकलता ही है और मुझे कुछ नहीं कहना है । जैसा मैं ने कहा, मुझे और कुछ नहीं कहना है, मेरा केवल यही कहना है कि हमारे फूड मिनिस्टर साहब जो स्टेटमेंट वगैरह करते हैं उन में गल्तियां और बिल्कुल मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होने चाहियें, जोकि अन्धे आदमियों को भी जरा सा देखने से मालूम हो जाय कि इस में गल्तियां हैं । उन का परिणाम केवल यही हो सकता है । उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि फलां-फलां जगह देखो, दाम कम हो गये हैं । उन्होंने कलकत्ते का उदाहरण दिया है कि वहां पर दाम कम हो गये, कानपुर का उदाहरण दिया है जहां पर कि हमारे स० मो० बनर्जी साहब बराबर रहते हैं । इसी तरह से कई जगहों के कोटेशन दे दिये हैं कि यहां यहां पर चीनी के दाम कम हो गये हैं, अब यह हमारे कंट्रोल में है । वह तो बहुत अच्छी बात है कि आप के कंट्रोल में यह चीज आ गई है, इस से अच्छी कोई और बात नहीं है परन्तु फूड मिनिस्टर साहब जानते हैं, पता नहीं हम को वह बतलाने को तैयार हैं या नहीं, लेकिन मैं उन से पूछना चाहूंगा कि आखिर कलकत्ते में दाम गिरने के कारण क्या थे ? आप ने इतनी चीनी जल्दी जल्दी वहां भिजवा दी । साफ है कि जहां पर माल अधिक आ जायेगा वहां पर दाम कम हो जायेंगे । परन्तु आप इस बात का खयाल रखें, यद्यपि वह जानते हैं कि उन को खयाल रखने की दरकार नहीं है । जो कुछ भी है उन की जानकारी में है, हो सकता है कि कुछ बातें न मालूम हों क्योंकि उन को शायद उसे देखने का वक्त न मिला हो तो मैं कहना चाहता हूं कि अब कलकत्ते से चीनी मुफस्सिल में जाती है, जैसे बर्दवान है, अन्य-अन्य जगह हैं, जिन के फिगर्स हमारे पास हैं, वहां पर दाम बढ़ जाते हैं । वहां पर दाम अभी भी ज्यादा हैं । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती होतीं तो बतलातीं कि वहां पर मुफस्सिल में दाम अभी भी काफी अधिक हैं । कलकत्ते में दाम इसलिये कम हो गये कि वहां पर चीनी चली गई । तो यह तो एक तरह की मिसलीडिंग चीज है ।

दूसरे मैं उन से यह भी पूछना चाहूंगा कि जहां पर दाम बढ़े हैं वह तो उन्होंने बतला दिये, लेकिन जहां पर अभी भी दाम बढ़े हुए हैं वे उन्होंने क्यों नहीं बतलाये ? सौराष्ट्र में दाम खूब बढ़े हुए हैं, राजस्थान में दाम बढ़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में बढ़े हुए हैं । मैं आप को आंकड़े दे कर बतलाता हूं कि इन जगहों पर कितने दाम बढ़ गये हैं ।

रायपुर (म० प्र०)	४७.२७ रु०
बिलासपुर	४६ ५५ रु०
राजस्थान	४७ रु० से लेकर ४९ रु० तक
सौराष्ट्र	५४ रु० से ५५ रु० तक

क्या यह मंत्री जी के लिये ईमानदारी की बात थी कि वे उन्हीं जगहों के आंकड़े दें जहां पर दाम किसी वजह से नीचे आ गये हैं और वे आंकड़े न दें जहां पर कहा जाता है कि दाम बढ़ गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य साहब पूछ रहे हैं मिनिस्टर साहब से लेकिन देखते हैं न उन की तरफ और न मेरी तरफ ।

श्री घुन्घुनवाला : इस का सम्बन्ध अधिकतर सभासदों से है इसलिये मैं उन की ओर देख रहा था । माफ कीजियेगा कि मैं आप की तरफ नहीं देख रहा हूं । मैं तो अपने सभासदों से यह कह रहा था जब इस तरह की बांचती हो रही है और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स सरकार की तरफ से सदन के सामने रक्खे जा रहे हैं तब सदन को सरकार से कहना चाहिये कि इस तरह की चीजें सदन के सामने नहीं आनी चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काशीनाथ पांडे । लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह विनती करूंगा कि वह दस मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें । अगर हर एक मेम्बर ऐसा इरादा कर के तो बहुत से मेम्बर बोल सकेंगे ।

श्री काशीनाथ पाण्डे (हाता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीनी की बिक्री के सम्बन्ध में जो माननीय खाद्य मंत्री का स्टेटमेंट हुआ है, उसे मैं ने बड़े ध्यान से देखा है और मैं यह समझता हूं कि आज जो समस्या हमारे यहां चीनी के दाम बढ़ जाने की है वह अगर इसी साल तक रहे तब तो गनीमत की बात होगी । लेकिन हम को इस बात पर विचार करना है कि क्या यह भाव इस साल तक रहेंगे, इस से और ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे । इस की क्या कोई उम्मीद है ? मैं इस बात पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखिर चीनी के दाम बढ़े क्यों ? इस के कारण क्या थे ? मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्रालय चाहे कोई स्टेप ले, लेकिन अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार वह दाम बने नहीं रह सकते । सप्लाई और डिमान्ड की थ्योरी बराबर इस बारे में भी लागू होती है । जब चीज जरूरत से कम होगी तो उस के दाम बढ़ेंगे और जब चीज जरूरत से ज्यादा होगी तो दाम घटेंगे ।

पंडित कु० चं० शर्मा (हापुड़) : यह आप सोलहवीं सदी की बात कर रहे हैं ।

श्री काशीनाथ पाण्डे : मैं तो पुराना आदमी हूं इसलिये वैसी ही बात कहूंगा । आप नई चीज बताइये ।

मैं एक चीज आप के अर्ज करना चाहता हूं । आज से दो साल से बराबर मंत्रालय के सामने यह बात आ रही है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में खुद यह दिया है कि ड्यूरिंग दि इयर १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी फैक्ट्री की थी वह थी १७.३ लाख टन, १८.७ लाख टन और २० लाख टन । लेकिन प्रोडक्शन क्या हुआ ? जिस साल कैपेसिटी कम थी उस साल प्रोडक्शन हुआ १९.२ लाख टन लेकिन जिस साल कैपेसिटी बढ़ गई थी उस साल प्रोडक्शन बहुत कम था १७.३१ लाख टन । उस साल प्रोडक्शन हुआ २२.२९ लाख टन दूसरे साल हुआ १९.७८ लाख टन और तीसरे साल हुआ १९.२ लाख टन । इस का मतलब यह है कि जो कैपेसिटी हमारी फैक्ट्रियों की है उस में भी अगर हमारे पास सप्लाई गन्ने की हो तो हम ज्यादा चीनी बना सकते हैं । बजाय इस के जो हमारी सेकेन्ड फाइव इयर प्लैन का टार्गेट था २५ लाख टन की कैपेसिटी का, उन्होंने यह भी दिया है कि फारेन एक्स्चेन्ज की कमी की वजह से उस कैपेसिटी तक भी हम नहीं जा सके हैं । लेकिन जो है उसमें थोड़ा सा ऐक्सपेंशन हुआ है लेकिन जो है उससे आप यह समझ जायेंगे कि जिस समय १७.३ लाख टन की कैपेसिटी थी उस साल हमारा प्रोडेक्शन हुआ है २२.९२ लाख । मैं यह कह सकता हूं अगर गन्ने की सप्लाई हमारे यहां हो तो चीनी हम जरूरत के मुताबिक पैदा कर सकेंगे । जो आंकड़े मिनिस्ट्री की तरफ से दिये गये थे इस साल के बारे में कि २१ लाख टन की हमारी कंजम्प्शन कैपेसिटी है, हम यह समझते हैं कि यह कैलकुलेशन हमारे खयाल से गलत है । कंजम्प्शन की कैपेसिटी हमारे देश की बढ़ गई है और वह के न एक सामंजस्य स्थापित करने के लिये दी गई है लेकिन अगर हम यही मान लें तो उसका नतीजा यह है कि हमारा जो

[श्री काशीनाथ पांडे]

प्रोडक्शन है वह १६.२ लाख टन है और जो कमी है उसका ज्ञान सारे कैपिटलिस्ट्स को है और उसका फायदा तमाम लोगों ने उठाया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो चीनी का प्रोडक्शन कम हुआ उससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि गन्ना कम था। हमारे देश में गन्ने की कमी नहीं है और गन्ने की कमी के कारण हमारे देश में यह क्राइसिस नहीं हुआ। मैं मिनिस्टर साहब के इस कथन को पहले तो समझ सकता था कि जो १ रु० ४ आने व १ रु० ६ आने मन गन्ने का दाम फिक्स किया है वह इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि कंज्यूमर्स को उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी मिले लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद आज चीनी किस भाव में बाजार में मिल रही है। मुहीउद्दीनपुर फैक्टरी की चीनी साढ़े १४ आने सेर मिलती है और वहां अब भी इसी भाव के कंट्रोल रेट पर चीनी मिलती है लेकिन फैक्टरी के बाहर चले आइये वहां चीनी १ रुपये और ६ नये पैसे प्रति सेर के भाव से मिल रही है। अब यह जो ३१ रुपये मन का भाव तय किया गया है उनसे ६ रुपये ४० नये पैसे कंज्यूमर्स को देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि मेरठ के आसपास ४२ रुपये और ४० नये पैसे मन चीनी बिक रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान गन्ने का दाम बढ़ाने की बात करता है तब तो आप कहते हैं कि हम उसको इतना बैलेंस्ड रखना चाहते हैं ताकि चीजों के दाम न बढ़ें लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किस के फायदे के लिये आपने यह ३६ रुपये चीनी का दाम तय किया है? हम लोग तो एक रुपये सेर की चीनी खरीद रहे हैं और ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार गन्ने का दाम क्यों कम बनाये रखना चाहती है?

पिछले साल जब खंडसारी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात थी तो हमारे अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने भावुकता में आकर उसका कड़ा विरोध किया था और सरकार की उसके लिये आलोचना की थी। मेरा निवेदन है कि जब कहीं किसी चीज की वजह से हमारी एकोनामी पर असर पड़े तो उस पर जरूर ख्याल करना चाहिये। जब खंडसारी इंडस्ट्री के बारे में कर्वे कमेटी ने लिखा है कि यह वेस्ट इंडस्ट्री है। खंडसारी की इंडस्ट्री स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज में एक वेस्ट इंडस्ट्री समझी जाती है। १०० मन गन्ने में खंडसारी केवल ६-७ मन निकलती है जब कि शुगर फैक्टरी में १०० मन गन्ने में १० मन चीनी निकलती है।

एक माननीय सदस्य: गुड़ के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री काशीनाथ पाण्डे: मैं मानता हूं कि गुड़ इंडस्ट्री को इनकरेज करना चाहिये लेकिन खंडसारी को तरक्की नहीं देनी चाहिये। मेरा तो ऐसा मत हो सकता है कि आप इस मत के न हों और आपका इसके विपरीत मत हो। जब तक खंडसारी उद्योग को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे जो अवस्था इस वक्त है अगले साल वह बेहतर नहीं हो सकती। आपने इस साल खंडसारी पर एक्साइज ड्यूटी तो लगा दी लेकिन इसकी प्राइस पर कोई कंट्रोल नही है और खंडसारी बहुत ज्यादा भाव में बिक रही है। अब जब खंडसारी ज्यादा भाव में बिक रही हो तो कोई चीनी मिल मालिक कोई फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी कोई क्रैडिट सोसाइटी तो चला नहीं रहे हैं, उन्होंने कोई धर्मशाला तो खोला हुआ नहीं है कि वह सस्ती दर पर चीनी बेचें। वह चीनी का जो व्यवसाय कर रहे हैं वह बिजनेस लाइंस पर कर रहे हैं जाहिर है कि जब उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा तभी वह इन मिलों को चलायेंगे वरना घाटा सहने के लिये थोड़े ही चलायेंगे। वह ब्लैक मार्केटिंग से भी नहीं डरते हैं। इसलिए सत्य बात को हमें ग्रहण करना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि ऐसे उपाय हम करें जिससे खंडसारी इंडस्ट्री को हम ठीक तरीके से कंट्रोल कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि फूड मिनिस्टर साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि

the main cause for shortage of sugar, drop in production has been mainly in Western U.P. due to poor crop and diversion of cane to gur and khandsari

हमारे देश में हर जगह गन्ना पैदा होता है लेकिन फूड मिनिस्टर साहब इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेस्टर्न यू० पी० की फैक्टरीज अपना क्रार्ट पूरे नहीं करतीं और यह बात सब से ज्यादा खंडसारी और दूसरी चीजों के बारे में कही जा सकती है। चीनी अगर कम बने तो उसका असर तमाम देश पर पड़ता है। माननीय सदस्य ने बतलाया कि ५५ रुपये मन चीनी सौराष्ट्र में मिलती है तो मैं समझता हूं कि इस में कोई गलत बात नहीं हो सकती। हम समझते हैं कि यह सत्य बात है और हम मिनिस्टर महोदय की राय देना चाहते हैं कि आप इस तरीके से प्राइस कंट्रोल करके चीनी की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और मैं आप से कह देना चाहता हूं कि शुगर फैक्टरीज के सामने अगले साल और भी क्राइसिस आयेगी अगर आप गन्ने का दाम नहीं बढ़ायेंगे। गन्ने के चूंकि मुनासिब दाम काश्तकारों को नहीं मिल रहे हैं इसलिये मैं देखता हूं कि गन्ने की एकेज क्रौप में भी कमी हो रही है।

दक्षिण में बम्बई में वहां पर ४ आने मन के हिसाब से गन्ने का दाम देते हैं। सिस्मा फारमूला के हिसाब से गन्ने के दाम ज्यादा मिलते हैं। वहां पर ईल्ड कम है और दूसरी बात यह है कि रिकवरी कम होने से और ईल्ड कम होने से किसान भी परेशान हैं। दूसरी तरफ वे किसान जिनको कि गन्ने के ज्यादा दाम मिलते हैं वे चीनी ज्यादा दाम में खरीदते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि फूड मिनिस्टर साहब को इस बारे में विचार करना चाहिये। समस्या गम्भीर है। चीनी के बढ़े हुए दाम कंज्यूमर देने को तैयार हैं बशर्ते कि उसकी कोई एक क्वालिटी हो। हम गन्ने के मुनासिब दाम काश्तकारों को दें ताकि शुगर फैक्टरीज में हम उतनी चीनी पैदा कर सकें जो कि हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी को देखते हुए काफी हो। यही मेरे चन्द एक सुझाव हैं।

श्री बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देश में जिस गति से चीनी की मांग और खपत बढ़ रही है उसके अनुसार हम चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम घनी खेती करें और गन्ने की क्वालिटी को सुधारें।

यह खेद का विषय है कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा करने के बाद भी सरकार इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करने में असफल रही है जिनमें गन्ने का उत्पादन और उसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में वृद्धि हो सके। श्रीमन्, मेरे चुनाव क्षेत्र में दो चीनी की मिलें हैं। मैं देखता हूं कि उनका उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलता। पहले कहा गया था कि वहां ट्यूबवैल्स लगाये जायेंगे जिनकी कि सिंचाई के परिणामस्वरूप गन्ने की पैदावार बढ़ेगी। बाद में वहां नहर लाने की बात हुई और आज स्थिति यह है कि नहर की नहीं आई और चूंकि नहर आने वाली थी इसलिये ट्यूबवैल भी नहीं लगे। नतीजा यह हो रहा है कि पैदावार घट रही है किन्तु यदि देश में उत्पादन कम है और मांग अधिक है तो यह स्पष्ट है कि हम ने वितरण की व्यवस्था ठीक रक्खी है और मेरा आरोप है कि खाद्य मन्त्रालय चीनी के वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं कर सका है।

इस सम्बन्ध में मेरी सब से पहली आपत्ति यह है कि जब देश में चीनी का अभाव था और मंत्री महोदय इस बात को अनुभव करते थे कि चीनी की खपत बढ़ रही है तो थोड़ी सी विदेशी मुद्रा के लोभ में चीनी को सबसिडाईज्ड करके, चीनी के निर्यात करने का जो निर्णय किया गया, मैं समझता हूं कि वह बड़ा गलत

[श्री वाजपेयी]

निर्णय था, अदूरदर्शितापूर्ण था और अव्यवहारिक था ।

देश की जनता अधिक मूल्य पर चीनी प्राप्त करे और हम चीनी को विदेशों में भेजें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिये मैं इसे कोई व्यावहारिक नीति नहीं मानता । विदेशी मुद्रा का महत्व है किन्तु आज चीनी सर्वसाधारण के जीवन का अंग बन गयी है, अब उसे विलास या ऐश्वर्य की वस्तु कह कर टरकाया नहीं जा सकता । चाय के साथ चीनी सुदूर गांवों तक पहुंच गई है, और यदि हमें अपने देश की जनता के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिये हमें अन्य मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये था । चीनी के निर्यात का विचार इस दृष्टि से बड़ा गलत साबित हुआ है । लेकिन जब चीनी के भाव बढ़ते हैं, बाजार में संकट उत्पन्न होता है । उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है, तो हमारी सरकार एक घिसा घिसाया, पिटा पिटाया उत्तर देती है और सारी जिम्मेदारी उद्योग और व्यापार पर डालकर अपना बचाव करना चाहती है । मैं जानता हूं कि उद्योगपति दोषी हैं, उन्होंने चीनी की अनुचित मुनाफाखोरी की है, और व्यापारियों ने भी जनता को लूटने में कोई कसर नहीं की है, मगर हमारी सरकार जो इस सदन से सब प्रकार के अधिकार प्राप्त कर चुकी है, कर सकती है । उद्योगपतियों और व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, वह सरकार संकट उत्पन्न होने पर इस सदन में आकर कहे कि इसके लिये व्यापारी जिम्मेदार हैं । उद्योगपति जिम्मेदार हैं । तो यह हमी की बात है । इस सदन ने सरकार को काफी अधिकार देने में संकोच नहीं किया । यदि उन अधिकारों के बावजूद सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियो पर नियंत्रण नहीं लगा सकी तो यह सरकार की दुर्बलता है । यह सरकार का दायित्व है । और सरकार जनता के रोष से बचने के लिये उद्योगपतियों या व्यापारियों को बलि का बकरा बना कर अपने पाप से बच नहीं सकती । मेरा निवेदन है कि जब सरकार के पास अनुचित मुनाफाखोरी को रोकने के लिये पर्याप्त अधिकार थे तो उनको काम में क्यों नहीं लाया गया । सरकार स्टाक जब्त कर सकती थी । क्या मिल मालिकों का या व्यापारियों का स्टाक जब्त किया गया ? कौनसा कदम उठाया गया उनके विरुद्ध ? मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है । और उसके दुष्परिणाम हमारे सामने है ।

दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि जब चीनी के भाव नहीं बढ़े थे, तब तक चीनी की जो मात्रा रिलीव की जाती थी वह मात्रा अधिक थी, लेकिन अप्रैल से जो मात्रा रिलीव की गयी वह कम कर दी गयी । २२ जनवरी सन् १९५९ को १ लाख ६५ हजार टन चीनी मुक्त की गयी थी लेकिन २९ अप्रैल सन् १९५९ को १ लाख ४० हजार टन चीनी मुक्त की गयी । मैं जानना चाहता हूं कि जब भाव बढ़ेंगे इस तरह के आसार बाजार में थे तो फिर चीनी कम मात्रा में क्यों रिलीव की गयी । इसकी छानबीन बहुत आवश्यक है ।

तीसरी आपत्ति टेंडर सिस्टम के सम्बन्ध में है । अनेक सदस्यो ने इस पद्धति के विरुद्ध बातें कही हैं । और मैं जानता हूं कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है । कोई नियम नही, कोई कसौटी नही जिसके आधार पर टेंडर के लिये प्रार्थनापत्र मंगाये गये । जिस किसी का भी प्रभाव लगा, सिक्का जमा वह अपना काम बना बैठे । और जो टेंडर सिस्टम से चीनी दी जाती है उसके भावों पर भी कोई नियंत्रण नही है । उन्होंने उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल किये । मैं समझता हूं कि इस सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए और इस में जो अनियमितताएं हुई हैं उनकी भी जांच बहुत आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक्स-फैक्टरी प्राइस तै की मगर वह प्राइस सभी प्रान्तों पर लागू नहीं होगी । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ प्रान्तों में चीनी के भाव कम तै किये गये, कुछ में अधिक तै किये गये, जिसके फलस्वरूप इधर उधर चोरी से चीनी भेजने को बढ़ावा मिला । इसके साथ ही जब एक्स-फैक्टरी प्राइस तै की गयी थी तो हमारी सरकार ने थोक व्यापारियो के लाइसेंस का विचार नहीं किया । एक्स-फैक्टरी प्राइस तै की गई थी पिछली जुलाई में और व्यापारियो को लाइसेंस देने की बात इस मई में की जा रही है । मै जानना चाहता हू सरकार को इतना समय क्यो लगा है । आज सरकार कहती है कि अगर चीनी के भावो पर नियत्रण रखना है तो यह बिना थोक व्यापारियो को लाइसेंस दिये नही हो सकता । मै जानना चाहता हू कि क्या पिछली जुलाई में सरकार इस बात का अनुभव नहीं कर सकी थी । अगर नही कर सकती थी तो सरकार ने दूरदर्शिता से काम नही लिया । पिछली जुलाई में जब चीनी की खपत बढ़ने के आसार थे और भावो में वृद्धि की आशका थी तो थोक व्यापारियो को लाइसेंस दे देने का काम होना चाहिए था, लेकिन वह नही किया गया ।

अभी खडसारी की भी चर्चा हुई है । हमारी सरकार ने खडसारी पर एक्साइज ड्यूटी लगायी, इसलिए कि गन्ना उनको न मिले और उससे चीनी बने । मगर मै कहना चाहता हू कि सरकार का यह प्रयत्न सफल नही हुआ । खडसारी के निर्माता जितना गन्ना चाहते हैं प्राप्त कर रहे हैं और एक्साइज इस्पेक्टर्स के साथ मिलकर एक्साइज ड्यूटी भी बचा रहे हैं । जब सरकार ने खडसारी पर एक्साइज ड्यूटी बढाई तो बाजार मे खंडसारी की कमी की वजह से चीनी का अभाव और भी अधिक अनुभव होगा इस बात का भी उसे ध्यान रखना चाहिए था । मगर उसने यह ध्यान नहीं रखा । और हम एक्साइज ड्यूटी के भी हाथ धो रहे है और उसके फल-स्वरूप चीनी की कमी के कारण जो भाव बढ रहे हैं उनके कारण भी कष्ट हो रहा है ।

गन्ने के मूल्य का भी सवाल आया है । पिछले साल खंडसारी वालो ने १ रुपया १४ आने मन पर गन्ना खरीदा जब कि मिल मालिक १ रुपया ७ आने से ज्यादा देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है । अगर गन्ने का मूल्य अधिक नही बढ़ाया जायेगा तो खडसारी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद भी मिलो को गन्ना नही मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप भावो को नीचे नही लाया जा सकेगा ।

सरकार चीनी का कन्ट्रोल करे या राशनिंग करे इस के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह आपत्ति दी है कि चीनी की खपत किसी के लिये अधिक, किसी के लिये कम है । इस मामले में लोगों में भेद है और सब धान बाईस पसेरी नही तोला जा सकता, सब को एक ही लकडी से नही हांका जा सकता । मेरा निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति की कम से कम आवश्यकता को तो पूरा किया जाय और इस के लिये सरकार को राशनिंग का सिस्टम अपनाना पड़ेगा । इस के सिवा कोई चारा नही है ।

अनेक सदस्यो ने बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं । कुछ आरोप माननीय मन्त्री महोदय पर हैं कुछ उन के विभाग के ऊपर हैं । लेकिन मुझे यह देख कर खेद हुआ है कि जो आरोप मन्त्री महोदय पर लगाये गये उन की पुष्टि में कोई बात नहीं कही गई । जहा तक विभाग पर आरोपों का सम्बन्ध है, मैं समझता हू कि इस सदन में जो अफसर अपना जवाब देने के लिये मौजूद नही हैं उन पर आरोप लगाना अच्छी संसदीय पद्धति नही है । लेकिन यह बात स्पष्ट है कि चीनी के गोलमाल के सम्बन्ध में जनता के मन में अनेक तरह के सन्देह हैं और सीजर की पत्नी की तरह से हमारे मंत्री महोदय को भी सभी सन्देहों से परे होना चाहिये । इस से अच्छा यह है कि

[श्री वाजपेयी]

जो कुछ भी सदस्यों ने आरोप लगाये हैं उन सदस्यों को निमंत्रित किया जाय उन आरोपों के ठोस प्रमाण देने के लिये, और अगर कोई प्राइमा फेसी केस बनता है तो सारे मामले को किसी हाईकोर्ट जज के सिपुर्द कर दिया जाय।

Shri Khadilkar (Ahmednagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to discuss this issue of sugar prices from a long-range point of view, because I do not think there is a short-term solution to this problem. As we all know, in 1946 and 1947, we used to get sugar at 13 annas a seer, but since then, taxes, excise and State levies have gone up—I am trying to analyse the factors which are beyond the control of the Ministry which go to increase the price of sugar. If we take the Central excise as it has increased in 1957, it works out at 17 nP. per seer. This is the increase in taxation. The quantum of tax on production was 14 per cent; now it has gone up to 36 per cent. The tax burden adding to the cost of production is passed on to the consumers. This is the present level. At the same time, there is a reduction in production to a large extent. But I do not understand one thing, though the Minister has given a statement. There was the last year's balance of 1·33 lakh tons. Why was it not made available to check the prices? That factor is not clearly mentioned in his statement. Why sugar production has gone down? This needs further explanation as the hon. previous speaker just now mentioned. As I said, you will have to find out some long-term solution. Sixty-seven per cent of the sugar production is more or less controlled by U.P. and the northern Indian areas. There, the method of production is outmoded; it is wasteful. As the Minister of Agriculture he must look into this.

The mills are almost dilapidated and the third factor which is operating is khandsari production. If at all you want to maintain a certain price level for the consumer you will have to take all these factors into consideration.

Another thing which has affected the price and to which serious thought must be given is export. As the previous speaker just now mentioned we are exporting 59,000 tons of sugar every year. But I do not think this export is profitable because if we compare the prevailing prices here with the prevailing prices in the international market, taking our cost of production into consideration, it is about Rs. 240 to Rs. 265 more than the international prices. If we calculate, by exporting this quantity of sugar, we are losing Rs. 1·25 crores annually.

I do not know what benefit the Food Minister is deriving from continuing this type of export and earning a meagre foreign exchange at the cost of the consumer, because, ultimately, this burden falls on the Indian consumer.

Certain taxes have gone up; railway freight rates have gone up, I admit. Production has gone down. That is also true. These are factors which are not under the control of the Ministry or the Minister. What is in his control? Has he performed that part of his duty whereby he could have checked the prices? Once you come to that basic thing, my first submission is that in our economy, if sugar or some other essential food material is in short supply, if, without having at your command a good control machinery, you begin to talk about it, our experience is that hoarders and speculators benefit thereby. So, unless we have got a controlling machinery of an overall nature—because we have learnt in the days when there was rationing—there is no use of having partial control. Control even at strategic points is never effective in the market. Either you must have a blanket control or no control at all. Then alone you can succeed in controlling the prices. Unfortunately, the Food Minister has not taken into consideration this basic factor which is

inherent and which has more or less entrenched itself in our market mechanism.

In this country the distributors are afraid that today or tomorrow, because of shortages, because of certain policy matters, there are likely to be controls and they are forewarned. They hoard the essentials and play in a speculative manner at the cost of the life of the common man and the poor man's life is being corroded further and further. This is the main thing.

It is no use pleading that we have less production. These things have happened. But within the means at your disposal why have you failed to control the market and guarantee a certain *minimum* price, which is reasonable under the given situation, to a consumer? Why allow the hoarders to hoard? What attempt was made to punish these people? We talk loud: 'We shall bring corruption to an end'. In righteous anger we sometimes utter these words. But if we examine the policies, in day to day life we find the greatest failure of the present Government so far as this aspect of our economy is concerned. The price levels of the daily needs of the people are left more or less to be determined by the trading community in this country. And this grip of the trading community over the policies of Government is, ultimately, bringing down the reputation of Government.

My hon. friends have said 'Here you own your moral responsibility as was formerly owned by the Railway Minister when there was an accident This is a social accident where everybody has suffered. Own moral responsibility and resign.' I do not think there is anything beyond that This is a type of moral responsibility which you must own and face the House and the country and make it clear that you will control this and will not allow speculators to dominate the market and play with the common man's life. This is one part.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must conclude.

Shri Khadilkar: I will finish in a minute, Sir.

On the 9th August, I presume, the Minister suggested that he is thinking of increasing the production capacity. In this country certain areas are good for production; and, particularly, south is very good. If he is considering the long-term aspect, if, from my own province of Maharashtra, he were to license 25 mills with the optimum production capacity, they will go into production in a couple of years and this headache of shortages will disappear within no time. Therefore, when you release new production capacity, I would urge that it should not be released in areas where the crop production is of an outmoded nature, where the sugar production machinery is also almost old and useless, and other factors operate to the detriment of increased production. It should be allocated to areas in this country where it will be utilised to the best advantage of the people at large.

Pandit K. C. Sharma: Mr. Deputy-Speaker, Sir, there has been enough rather unnecessarily hard criticism of the policy of the Government and the failure in its implementation. Therefore, I would not repeat what is unnecessary. I would simply beg to point out that in a developing economy many things happen which you do not expect

For instance, the consumption has increased. Nobody expected that the consumption would increase to the extent it has done. Whoever be the Food Minister, he cannot bring sugar or grain from his pocket. Mistakes are bound to occur as they have occurred. They have occurred because there was no pressure and the hon. Minister does not claim to be a genius. It is the genius alone that meets an unexpected crisis successfully when it meets with unexpected crisis. An ordinary man in office with

[Pandit K. C. Sharma]

a rationalised discipline at his back, at the most, can avoid what is called a breaking down of the administration, and so much the hon. Minister can safely claim.

The fundamental proposition that I would like to point out is the proposition of production. What is wrong is that we take things as they are. In any developing economy there is no order like the military order 'as you were.' If you order the economic development process like a military colonel 'as you were', there will be failure; here lies the crux of the problem. A great philosopher has said: every day you go to bed, the old man is dead; every day you wake up in the morning, you are a new man. Every financial year that passes should be left like that and every new year that is coming should be taken as a year of progress and change and new measures should be taken. Therefore, I would request him to consider seriously this thing. I have full faith in his capacity, young as he is and resourceful enough as he is. He can do the job. He should take it up seriously and take strong measures to see that a new variety of sugarcane is produced next year. Look at the cane going to the mill. What will the mill-owner do with some of that rotten sort of cane, without any juice inside? The result is that the cane fails to give the mill owner the necessary quantity of juice Therefore, he does not worry even about minimum facilities and gets the cart unloaded after 36 hours. What is the consequence of it? This sort of treatment is nothing but slavery. On this criterion I say that this great State of ours has no face to boast before the comity of nations that we are a civilised people. The poor peasant has to wait for 36 hours. Where is independence for that man? Where is your safety or liberty? Where is the protection of the man? This is the consequence. Bad production is at the root; these are the consequences that affect the very roots of civilised society. Therefore, I urge him to take strong measures to have a better variety of sugarcane and raise the price. Make it compulsory for the mill-owner to provide good manure and seed and give every help to the cultivator; the better variety of sugarcane will come and producer will get better price. Demarcate an area for the mill and beyond that you may allow khandsari and gur. But make it compulsory for the mill-owner that in the area allotted to him, he shall have to pay for every pound of cane that is produced. Cane is burnt? Who is responsible? Cane is not produced merely by the wish of the man. Money and labour had to be spent on it. When the cane in the field is burnt, what happens? The man is ruined. Who is responsible for the ruination of the peasant? Therefore, take the production to a scientific level and take things seriously and take strong measures. Young as you are, if you put in your intellect and physical capacity to the job, you will do it. I mean to say nothing further, Sir.

Shri A. P. Jain: Sir, I am not going to plead before this House that there has not been profiteering in sugar The mill-owners, wholesalers and the retailers have all unduly benefited. The question is whether in the circumstances Government have or have not done anything to control the price of sugar, whether they have succeeded to any extent. In the note which I had circulated to the hon Members, I have stated that the sugar situation had improved but it was not yet fully under control. There are two kinds of questions involved. One is the question of policy. Some allegations may have been made that we have deliberately followed a policy with a view to help the sugar mill-owners. If that is so, it is a very great charge and if we can be held guilty of that charge, I am not fit to occupy this place and I will resign. The second type of charge may be that there has been corruption in the department, etc. It is not with my permission that corruption has taken place. I am prepared to

look into it and I will say something about it a little later.

The first question is about the availability of sugar. In the paper, we have said that the availability of sugar is not sufficient during this year. Hon. Members have given certain figures. I am sorry to say that those figures are incorrect. I will first take up the question of the availability of sugar in 1956-57. The carry-over in that year was 5·32 lakh tons. The production was 20.29 lakhs and altogether the availability was 25.61 lakh tons. The consumption was 19·46 lakhs, export was 1·44 lakhs. In 1957-58, the carry-over was 4:31 lakh tons. Production was 19·78 lakhs; thus the availability was 24:09 lakh tons. Consumption was 20·42 lakh tons; the export was ·36 lakh tons, leaving a balance of 3·31 lakh tons.

Shri S. L. Saksena: About khandsari?

Shri A. P. Jain: I am not including khandsari now; I am coming to that later on. The carry-over this year was 3·31 lakh tons. Some hon. Members have stated that there was some sugar in the ships Where is the sugar in the ships or ports?

Shri Khushwaqt Rai: I never mentioned ships; I mentioned ports and markets

Shri A. P. Jain: There was no availability of sugar at the ports. What was available was only this: 3·31 lakh tons with the mills.

Shri S. L. Saksena: I will quote from the *Indian Sugar Manual*. There were 85,000 tons in the inland markets, 14,200 tons in the ports and 4,58,939 with the factories.

Shri A. P. Jain: It cannot be so.

Shri S. L. Saksena: It is here on page 89

Shri A. P. Jain: The hon. Member may pass it on to me. It is true that at that time there was a little imported sugar available. This year, there was no import of sugar. Some of this was carried over.

Shri S. L. Saksena: It is all last year's production.

Shri A. P. Jain: It was 57-58 production; I am talking about 58-59. It is a fact that the carry-over was 3:31 lakh tons. The production was 19·21 lakh tons. So, the total availability of sugar during this year was 22·52 lakh tons. The consumption of sugar in this year is expected to be 21 lakh tons and the exports would be 25 thousand tons. So, the carry-over at the end of the year would only be about 1·23 lakh tons for 1959-60. Ordinarily, a safe carry-over is about 3-4 lakh tons because the new sugar year begins from the 1st of November and the factory-produced sugar is released only by the middle of December. The new sugar is ordinarily released in the month of December, after the 15th of December, and the previous year's carry-over is consumed during November and December. So, on all hands it has been accepted that the safe carry-over is 3 to 4 lakh tons. This year we will have a carry-over of 1.23 lakh tons only. While the statement I made on a previous occasion that we had sufficient sugar for consumption this year is correct, nonetheless it is a fact that the carry-over next year will be only about 1 lakh or 1¼ lakh tons as against 3·31 lakh tons this year. Therefore, it will have to be accepted that though we have got enough sugar for consumption during this year, our position is a tight one. No one can deny that.

An Hon. Member: Is it on the basis of estimated production?

Shri A. P. Jain: It is now practically firm. Because, the special season produces only 15 thousand tons of sugar, and the production up till now has been 19·05 lakh tons. So it will not exceed that.

[Shri A. P. Jain]

Another thing has been said, that in the releases of sugar we have manipulated in a manner as to create a scarcity. I will place before the House the figures of releases in the year 1958 and this year. In the month of January, in 1958 the release of sugar was 1,68,000 tons; but this year the release is 1,92,000 tons, that is 24,000 tons more. In the month of February, the release was 1,83,000 tons last year; this year it is 1,84,000 tons. In the month of March, last year the release was 1,84,000 tons; this year it is 1,85,000 tons. In the month of April the release was 1,76,900 tons last year, and this year it is 1,69,000 tons; that is only about eight thousand tons less. In May last year there was a big release. The normal release was 1,69,000 tons. But when the sugar market went out of control and the price began to go up—this matter was also raised in this House—we gave a special release of 1 lakh tons. This year we have released 1,70,000 tons which compares favourably with the normal release. This year our stock position was not such that we could give a special release. If I had any sugar I would have given a special release. So, although in May last year two releases were given, one of 1,69,000 tons and another of 1 lakh tons, this year only one release of 1,70,000 tons was given And I plead before the House that the special release of 1 lakh tons could be done only because plenty of sugar was available that year. This year it was not available, and I could not.

Shri S. L. Saksena: There was enough sugar in your stock, but you did not do it. That was a crucial mistake.

Shri A. P. Jain: There was no mistake. In the month of June last year the release was 1,73,000 tons. This year the release is 1,88,000 tons.

In other words, during the first six months of 1959 we have released 10,88,000 tons. Multiply it by two, and the total consumption comes to 21.76 lakh tons. Can it be said that these releases had been manipulated in a manner so as to assist the mill-owners? I only want the House to judge on the basis of the facts, hard facts which I have placed before it, whether the releases have been manipulated in any manner whatsoever.

Shri S. L. Saksena: The mistake was made when the sugar price rose to Rs. 9 and Rs. 10.

Shri A P. Jain: I have already said that last year in the month of May we gave a special release of 1 lakh tons when the prices began to rise. This year we could not afford to do it because of the reason that our sugar position was very tight.

Shri Braj Raj Singh: Is it not a fact that last year the special release was made only for the reason that the season was summer and also marriage season?

Shri A. P. Jain: It was made because the prices were going up.

Shri Subbiah Ambalam (Ramanathapuram): May I know why Government could not ban the export of sugar?

Shri A. P. Jain: I am coming to that. Take the question of export The House is well aware that we need foreign exchange badly. And, therefore, we decided on a policy of export of sugar, with the approval of the House. This year we decided to export 1 lakh tons of sugar. That was based on the original estimate. Our estimate of production this year was 21 lakh tons, and with a carry-over of 3·31 lakh tons we were expecting that we shall have a total quantity of 24.31 lakhs at our disposal.

Shri S. L. Saksena: What was the basis on which that assumption was

made when there was actually less sugarcane?

Shri A. P. Jain: That was the estimate. It did not come out to be true. When we came to know that the sugar position was tight and we shall not have much surplus of sugar, we reduced the quantity to be exported from 1 lakh tons to 25,000 tons.

Shri S. L. Saksena: When?

An Hon. Member: In July.

Shri A. P. Jain: We have exported only 9,000 tons out of the 25,000 tons. So, it is not that we did not take that step. We did take that step to reduce the quantity of exportable sugar.

Shri S. L. Saksena: What was the amount in April when the price was rising? You knew in February. (*Interruptions*)

Shri A. P. Jain: We took a decision and we announced it. (*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker: Order, order

Shri A. P. Jain: Another question has been raised about the system of allotments During the first four months, that is December 1958 to March 1959, the system was to receive the applications by hand. Immediately on receipt, a priority number was assigned to each applicant in the presence of the applicant. These were then entered in a register, and then on the basis of the priority entry in the register the allocations were made. On the 28th March, 1959 there was a huge crowd which collected and the police had to be summoned. Therefore, the system of receiving applications by hand was given up and the applications from 30th March, 1959 were received through registered post, accompanied by a *chalan* of deposit.

Shri Subbiah Ambalam: May I know whether these applications were received at New Delhi or.....

Shri A. P. Jain: Yes, at New Delhi.

Shri Subbiah Ambalam: For the whole of India?

Shri A. P. Jain: Yes, for the whole of India.

And priority numbers were assigned on the basis of the delivery memo received from the post office. After assignment of priority numbers the applications were scrutinised by a committee of three senior officers of the Directorate

An Hon. Member: Very nice!

Shri A. P. Jain: Ordinarily we have been allocating 2 per cent. of the sugar for the purposes of allocation direct by the Government. This system continued right up to April, and at that time sugar was allotted to certain areas—because it was a comparatively small quantity—where the prices had a tendency to go up It was done in some big towns of U P and other big towns were selected; among these were Calcutta, Kanpur, Delhi, Bombay. And when the prices began to go up in the Punjab all the towns with a population of more than a lakh were also selected

These are the various operations through which sugar has been distributed, which are generally the normal operations and about which I have mentioned.

As a result of the rise in sugar prices which happened about the end of April and the beginning of May we took the following steps: Firstly, in order to control sugar or any other commodity it is first necessary to find out the persons whom you are going to control and that can be done only through the system of licensing On the 7th of May we issued a letter to the State Governments requesting them to take action to license the wholesale dealers. I want to make it clear to the House that the licensing of the dealers takes more than a month;

[Shri A. P. Jain]

because, firstly, a notification has to be issued and you have to give at least fifteen days or more time for the people to make applications. After they have made the applications, each of the applications has to be scrutinised and then a licence has to be issued. Now, as a result of the issue of this letter on 7th May the wholesalers could be licensed by the middle of June and in some cases they could not be licensed by the middle of June. Therefore, we could not take over the entire sugar for distribution through the wholesale dealers, because if we had taken it over than anybody who came would have got the sugar, whether he was a wholesale dealer or not, and he would have misused it. Therefore, when we practically decided upon control of sugar the first thing that we rightly did was to license the wholesale dealers. The system of licensing in a major part of the country was finished by the middle of June, but in some parts of the country it was done a little later.

15 hrs.

Therefore, Sir, one thing follows, that we could not exercise any rigid control over the release in the month of May because the release in the month of May was made near about the 23rd of May—22nd, 23rd or 24th. In the month of June, when the wholesalers had been licensed, we took over the entire production of Punjab and 70 per cent of the production of U.P. and North Bihar for purposes of allocation by the Government. The reason why we left 30 per cent in these two regions of U P. and North Bihar was that registration had not been completed in all parts of the country and, therefore, if we had taken over the entire sugar for allocation direct by the Government there might have been a great scarcity of sugar in places where licensing had not been done.

Now, in the month of July we have taken over the entire production in the controlled regions of Punjab, U.P. and North Bihar for the purpose of direct allocations. The position today is this. . . . .

Shri S. M. Banerjee: Sir, may I ask one question?

Shri A. P. Jain: I will answer questions later. The position today is that no movement of sugar from one zone to another is allowed. In the north of India each State is a zone and in the south the four States constitute a zone. Sugar is allotted to each zone according to its requirements but on the basis of its past consumption. For instance, in the case of Uttar Pradesh we found that normally Uttar Pradesh was consuming 25,000 tons of sugar and so we allocated 25,000 tons of sugar to Uttar Pradesh. In the case of Bombay we found that the annual consumption of sugar in that State was of the order of 5 lakh tons Bombay has produced 3,20,000 tons in its own territory, and therefore we assigned 1,80,000 tons from U.P. to make up the deficit. Similarly, sugar has been allotted to all the regions according to their requirements worked out on the basis of their consumption.

Shri Easwara Iyer (Trivandrum): What about the south?

Shri A. P. Jain: I will explain why certain regions are controlled and others are not controlled. Now, no free quota for sale to factories is available in the controlled regions As soon as an allocation is made, information is communicated to the State Government and to the Collector of the District concerned that so much sugar has been allocated to such and such a person. Distribution inside the State is made according to the advice given by the State Government. The State Governments are at liberty to distribute it through cooperative societies, they are at liberty to distribute it through associations of merchants, they are at liberty to distribute it through licensed dealers,

but not through other persons. So far as the wholesale licensed dealers are concerned, the State Governments inform the Centre that so much sugar should be allotted to each District, which is accordingly allotted. The State Governments also send the name of the wholesaler to whom the sugar should be allocated. So, Sir, the position today is that sugar is being allocated on the basis of past consumption of the different States according to the directions given by the State Governments.

Then, the sale price of wholesale dealers is also controlled on the following basis: ex-factory price, plus cost of transport, plus local taxes such as octroi etc., and up to Re. 1—not exceeding Re. 1—for profit, handling and incidental charges. The Collector, after taking these things into account, is given the power to declare a price for his District.

Therefore, today the position is that in the controlled regions the mills are not allowed to sell any sugar on their account. It is the Government of India which allocates the sugar to a particular person and the mills sell at the controlled price. Even the wholesale price is fixed; of course, we have not fixed the retail price because I do not know whether it will be wise for us to fix the retail price

A question has been put as to why we have not controlled the prices in the whole of India and why we have selected certain regions for controlling prices leaving the other regions In particular, the case of South Bihar has been pointed out. Hon. Members will remember that the system of controlling prices was taken up in the month of April, 1958. When the prices in North Bihar and Uttar Pradesh were fixed, Rs. 36 per maund was fixed as the controlled price and Rs. 36-8-0 was fixed as the controlled price in Punjab.

Shri Braj Raj Singh: It was in July, 1958, I believe.

Shri A. P. Jain: I stand corrected. At that time we found that in the case of South Bihar the cost of production worked out to Rs. 37|29 nP, whereas the selling price in the market in the month of April, on the basis of which these controlled prices were fixed, was Rs. 36|25 nP.

Shri S. L. Saksena: What is the basis of those figures?

Shri A. P. Jain: These are figures that have been calculated. In the Control Order it was said that the Central Government may from time to time by notification in the official Gazette fix prices or maximum prices at which any sugar may be sold or delivered, and different prices may be fixed for different areas, factories or different types or grades of sugar; such prices or maximum prices shall be fixed with due regard to the prices or minimum prices fixed for sugarcane, manufacturing cost, taxes, reasonable margin of profit for producer or trade and any incidental charges. If we had fixed the prices for South Bihar at that time, we would have made a gift of Rs. 1|04 nP. to the factories of South Bihar because, as the hon. Members are well aware, when a controlled price is fixed that generally becomes the normal price and sales do not take place at a price lower than that. That is the general experience. If the selling price at that time was Rs. 36 25 nP. and the cost of production was Rs. 37'29 nP., certainly we would have made a gift of 1|04 nP. to the factories of South Bihar if we had fixed the prices in South Bihar.

Shri S. L. Saksena: The U.P. Government has said in the Assembly that the cost of production was Rs. 33 only.

Shri A. P. Jain: Those figures are wrong; they have themselves said that those figures are wrong.

Then, why have we not controlled the prices in Bombay and South India? Bombay is a highly deficit

[Shri A P Jain]

State so far as sugar is concerned. Its annual deficit is of the order of 1,80,000 tons. Though South India has now become almost self-sufficient, it was a deficit area in the past. The prices both in Bombay and in South India are determined by the ex-factory price of sugar in U P and Bihar, from where sugar is exported to these centres, plus the cost of freight Therefore unless we had taken the entire distribution into our hands it would have been impossible to fix prices in respect of the factories in the south because it is not the cost of production in the factories in the south and in Bombay which determines the market price there but it is the landed price of sugar imported from Uttar Pradesh which determines the price in Bombay and South India

Now, the Southern India Mill owners' Association worked out a scheme even, I think, in the month of May for controlling the prices, and they fixed the issue price on the basis of the landed cost of sugar from Uttar Pradesh

Shri Subbiah Ambalam Are we to understand that the prices of sugar in the South were fixed in relation to the Uttar Pradesh prices? I may inform the Minister that with the announcement of the Government about sugar control and the announcement about licensing to sugar dealers the prices shot up by 20 per cent in the South

Shri A. P Jain According to my information, normally, the market price in the south is determined by the landed cost price of sugar in the South from Uttar Pradesh

Shri Subbiah Ambalam: May I know the ex factory price of sugar produced by the distilleries in the South and by the manufacturers in the south prior to control?

Shri A. P. Jain: I do not have the figures at present. I can give them if he wants later

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Anybody can know the prices prevailing in the market. The hon. Minister's figures are based on what? Nobody knows.

Shri A. P. Jain: What I said was about the basis on which the market prices are determined

Shri S. L. Saksena: Does the hon Minister know that the late Shri Kidwai fixed the price of Rs 30 all over India including Bombay and Calcutta?

Shri A P. Jain That was for imported sugar

Shri S. L. Saksena. For the sugar produced in this country

Shri A. P. Jain. Now, I may say that even now there are some cases pending I think some cases have been decided Sugar was requisitioned and the Government had to pay a higher price because the contention of the millowners was that they should get a price on the basis of their cost of production whereas the Government did not want to do it The case was decided in their favour That is why we did not fix the control price for the whole of India These three regions, that is, Punjab, Uttar Pradesh and North Bihar, produce about 70 per cent of the sugar produced in the whole of India and we were quite justified in concluding that if we can fix the price of 70 per cent of the sugar the other prices will be controlled, and in fact, for a long period, they were controlled But when the prices in Uttar Pradesh went up the prices in the South and in Bombay also went up and when prices in Uttar Pradesh and Bihar have been controlled now, sugar is being supplied at ex-factory rates and the prices are normal

श्री अजित राय (पटियाला) : जो कदम—स्टेप्स—आप ने मई में उठाये, क्या वे पहले नहीं उठा सकते थे ?

Could we not have taken those steps in February when the warning was given in the House?

Shri A. P. Jain: Hon. Members from the other side....

Shri Narayanankutty Menon: From all sides.

Shri A. P. Jain.....spared no criticism. But the first time when sugar prices began to go up and a scare created was about the end of April. It was on the 7th of May that we issued letters to the State Governments to undertake licensing of sugar dealers.

There is also another aspect of it. Unnecessary licensing and unnecessarily creating scare is not a good thing.

Shri S. M. Banerjee: When the question was mooted in this House.

Shri A. P. Jain: Even before I made the statement in the House we had issued instructions to the State Governments to license the wholesale dealers. This is so far as the policy is concerned and so far as the steps taken by us are concerned.

Shri Subbiah Ambalam: I want to offer only one point for being explained. The hon. Minister said that there was an announcement regarding the control of sugar and licensing. May I know whether before the announcement was made, the Government took care to requisition the entire stock available with the millowners?

Shri A. P. Jain: No, Sir. That is because we had no machinery for distribution. Before we requisition the stock we must have machinery for distribution and in the month of April we created a machinery for distribution and by the end of July we had taken over the entire sugar.

Shri S. M. Banerjee: One clarification. It is pertinent in this case. The Minister, in his statement, said:

> "While these control prices were generally effective till April 1959 when the prices started rising, there were reports that most of the factories were charging higher prices, without of course revealing them in their books which would have enabled legal action to be taken."

I want to know whether there was any action taken. I want to know why no action was taken when it was definitely known that they were charging higher prices.

Shri A. P. Jain: No specific case....

Shri S. M. Banerjee: Am I to take it that no reply to my question was given?

Shri A. P. Jain: Four specific cases of the violation of the law were reported to us. We prosecuted two people. In the other two cases, the persons who had sent the telegrams of the first information were not prepared to give evidence. One of these cases has been decided by the Calcutta courts and the other case is pending. A large number of persons wrote to us. One of the hon. Members who is a party to this motion met me and made some complaint. I told him, "Give me a specific case and I will prosecute the person concerned". I know that a big racket was going on and that profits were being made. When it came to a question of evidence we were not getting the evidence. We wrote to the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar to depute their police to detect those cases. They could not send us any case. Here, we tried to detect cases through the Special Police Establishment. They said that unless some specific facts were given to them and any particular case entrusted to them they could not carry on any enquiry. I know profits had been made. I am very unhappy about it. It is most unfortunate that there should have been so much of profiteering by the millowners, by the wholesalers and

[Shri A. P. Jain]

by the retailers, and in the circumstances, we could not control it.]

An Hon. Member: Resign

Shri A. P Jain: With the various steps that we have taken, the situation is coming under control and I hope and wish the position will improve

There is one thing more Hon Members have said that there has been a lot of corruption I would not like to defend any corruption I want hon Members to give me at least some facts I do not say, "all the facts". It cannot be a roving enquiry If I am given some facts, I will look into the cases, and see whether there has been any corruption in the allocation or whether there is anything fundamentally

Shri S L. Saksena: I shall give all the evidence that is available with me

Shri Subbiah Ambalam: It is not a question of corruption From the policy of the Government as seen from the statement of the Minister, it is clear that the Government have not cared to take adequate steps before announcing the programme You allowed them and created a situation for them to indulge in corrupt practices and sell all the stocks in the black market

Mr Deputy-Speaker. Am I charged with this allegation?

Shri A. P. Jain: Some hon Members said that I was constitutionally responsible If there is any charge against me, I am prepared to stand a trial, and I am prepared to resign I will not stand here for a minute (*Interruptions*)

Shri S L Saksena: Appoint a Commission

Shri A. P. Jain: If it is a question of anything having gone wrong in the Directorate, well, I am prepared to look into it

Shri S. M. Banerjee: Appoint a Commission

Shri A P Jain: There is no case for the appointment of a Commission You may charge me I am here, and I have explained the policy You may not agree with it, but I maintain that these are the correct policies. The House is the judge of the policies.

Shri S M Banerjee: It is no policy; it is polishing

Shri A P. Jain: If, on the other hand, there has been any corruption on the part of any officer or any official, he must be punished Nobody could give him any shelter But this kind of sweeping charge that Rs 25 lakhs

Shri Braj Raj Singh May I ask whether any regulations were made for announcing tenders accepting tenders, etc? May I know whether any information was published in the press or whether any such thing was pasted on the notice-board of the Sugar Directorate?

Shri A P. Jain. No These rules were laid down from time to time I am prepared to pass on a copy of these rules to the hon Member

Shri Nagi Reddy (Anantapur) What is the use?

Shri A P Jain. For the purpose of allocation But they are not published in the gazette If any allocation has been made against these rules and which gives rise to suspicion of bribery or corruption, certainly action can be taken in those matters So, the position is clear

Shri Narayanankutty Menon: May I ask how many crores of rupees has the AICC received during the last elections from these millowners alone in Uttar Pradesh? The highest form of corruption

Mr. Deputy-Speaker: It is not for the Minister to know or to tell.

Shri A. P Jain: I know there is a lot of sentiment and passion about it I know that the situation has been bad I know that it has not fully come under control as yet, but I maintain that things have been improved We are doing our best and we hope that sugar will come fully under our control After all, the key to the maintenance of proper prices is production This year, as I said, the main cause for the rise in price of sugar was low production Some suggestions were made for increasing production We will give due consideration to them, There will be utmost effort on our part to increase the production of sugar, so that these difficulties may not arise

Shri Braj Raj Singh: In view of the serious situation, can he categorically say that no exports are going to take place in the future months?

Shri A. P. Jain: The maximum quantity fixed for export is only 25,000 tons, out of which we have exported 9 000 tons We will make our utmost effort to reduce the export to the minimum and we shall try to export as little as possible just for maintaining certain markets We had a demand of about 60 000 maunds of sugar from Nepal We could not refuse them and we supplied it Except for these exceptional cases, we are not allowing exports

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) माननीय मंत्री ने जैसा अभी कहा और माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि मुनाफाखोरों ने मुनाफा उठाया । क्या इस सम्बन्ध में किसी तरह का कमिशन अप्वाइंट करने को सरकार तैयार है ? दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हू कि शुगर के डिस्ट्रिब्यूशन के लिये कोई पापुलर कमेटी के निर्माण का, जिस में हर दल के लोग हो, कोई विचार है या नही ?

श्री अ० प्र० जैन जहा तक पहले सवाल का ताल्लुक है, मैं ने खुद कहा कि उन्होंने मुनाफा कमाया लेकिन उन का जो कुछ भी भला बुरा किया जा सकता है वह अदालतों में मुकदमा चला कर ही किया जा सकता है । जब भी कोई केस होगा, मैं वादा करता हू कि उन का प्रोसीक्यूशन किया जायेगा । जहा तक पापुलर कमेटी वगैरह का सवाल है, डिस्ट्रिब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और वह इस को देखेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय मेरा मतलब कोई सलाह वगैरह देने का तो नही है, लेकिन जिन्हो ने इस बहस में हिस्सा लिया है अगर उन को बुला कर मिनिस्टर साहब एक कमेटी में बैठ जायें तो जो बहुत सी शिकायात हैं वह पेश की जा सकती हैं और दिक्कतो को आसानी से हल किया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य और जिन्हो ने हिस्सा नही लिया है वह क्या करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय जो हिस्सा नही ले पायें हैं वह भी जा सकते हैं ।

श्री अ० प्र० जैन जो इस में दिलचस्पी रखते हे या यह समझते हैं कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है मै उन सब को दावत देता हू कि वह आ कर बातचीत क ।

Shri S. L. Saksena: Why have you stopped the export of khandsari from U P to Rajasthan?

श्री अ० प्र० जैन जा मिल की शुगर है वह भी चली जायेगी । बड़ा मुश्किल है इस की शिनाख्त करना कि वह न जा सके इस के साथ ।

श्री सुब्बबक्त राय श्रीमान्, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो प्रश्न आज प्रातःकाल मैं ने यहा उपस्थित किया था उस पर हमारे सभी भाइयों ने चाहे वे इधर बैठते हों चाहे उधर बैठते हो, चिन्ता प्रकट की और माननीय मंत्री जी ने भी यह माना है कि इस शुगर के मामले मे मिलमालिकों ने, थोक चने वालों ने और फुटकर बेचने वालों

[श्री खुशवक्त राय]

ने भी बेइन्तहा रुपया कमाया है । जब इस बात को मान लिया गया तब मैं नही समझ पाता हू कि माननीय मत्री जी को इस में क्या परेशानी है कि एक कमीशन आफ एन्क्वायरी नियुक्त कर दिया जाय । मै समझता हू कि माननीय मत्री जी को अपने ख्याल से और सदन की इच्छा के ख्याल से, इस देश में जो चिन्ता पैदा हो गई है उस के ख्याल से इस माग को मान लेना चाहिये । यह मांग इधर से ही नही की गई है, उधर के लोगो ने भी यह माग की है कि कमीशन आफ एन्क्वायरी बनाया जाय और उस के जरिये यह जाच कराई जाय कि किस तरह से लोगो ने फायदा उठाया ।

इसी के साथ-साथ जो आरोप डाइरेक्टोरेट पर लगाये गये है वह भी बडे गम्भीर हैं और उन के ऊपर भी विचार किया जाना चाहिये । उन को यह कह कर नही छोडा जा सकता कि जब तक आप के पास केस न आयें आप कुछ नही कर सकते । यहा पर ऐसी बातें कही गई हैं कि उन की जाच होनी आवश्यक है । इसलिये मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय मत्री जी से यह कहुगा कि जो अमेंडमेंट प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने दिया है उसे मैं मजूर करता हू और उन से भी प्रार्थना करता हू कि वे इस बात को मान ले

श्री अ० प्र० जैन : मैंने कोई एन्क्वायरी की बात नही कही । मैंने कहा कि आप सब लोग आइये, बैठ कर बातचीत कीजिये । कोई बात ऐसी मालूम होगी कि डाइरेक्टोरेट मे ऐसा हुआ है तो जरूर ऐक्शन लिया जायेगा ।

Mr. Deputy-Speaker: After the reply of the mover, the debate is closed I shall put the amendments I shall first put Amendment No 1 by Shri S L Saksena

The question is

That at the end of the motion, the following be added, namely —

and recommends that a High Power Commission of Enquiry, consisting of either a Supreme Court Judge or an eminent public man be appointed to investigate into the complaint, and to find out the causes of the present sugar racket which has already resulted in the exploitation of sugar consumers to the extent of Rs 16 crores during the last five months and the evasion of income-tax on the profits so accruing to the sugar mill-owners"

Lok Sabha divided Ayes 32, Noes 84

Division No. 1] AYES **15.32 hrs]**

Awasthi, Shri Jagdish
Banerjee, Shri S M
Basumatari Shri
Chakravartty, Shrimati Renu
Dige, Shri
Dwivedy, Shri Surendranath
Elias, Shri Muhammed
Goray, Shri
Gupta, Shri Sadhan
Iyer, Shri Easwara
Kamble Shri B C
Kunhan, Shri
Mahendra Pratap, Raja
Mehta, Shri Asoka
Menon, Shri Narayanankutty
Mullick, Shri B C
Pandey, Shri Sarju
Panigrahi, Shri
Parulekar Shri
Patil, Shri Balasaheb
Patil Shri U L
Rai, Shri Khushwaqt
Ram Garib Shri
Rao, Shri D V
Rao, Shri T B Vittal
Reddy, Shri Narapa
Saksena, Shri S L
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Shri Braj Raj
Singh, Shri P N
Tangamani Shri
Vajpayee Shri
Verma Shri Ramji

NOES

Azad, Shri
Ambalam, Shri Subbiah
Arumugam, Shri R. S
Arumugham Shri S R
Balmiki, Shri
Barupal, Shri P L
Basappa, Shri
Bhagat, Shri B R
Bhargava, Pandit M B
Bhargava, Pandit Thakur Das
Chettiar, Shri Ramanathan
Chuni Lal, Shri

Das, Shri K. K.	Mandal, Dr. Pashupati	Sahu, Shri Rameshwar
Das, Shri N. T.	Maniyangadan, Shri	Saigal, Sardar A.S.
Desai, Shri Morarji	Masuriya Din, Shri	Samanta, Shri S.C.
Dube, Shri Mulchand	Mathur, Shri M.D	Sarhadi, Shri Ajit Singh
Eacharan, Shri V.	Mishra, Shri Bibhuti	Satyabhama Devi, Shrimati
Ganapathy, Shri	Misra, Shri R. D	Sharma, Pandit K. C
Ganga Devi, Shrimati	Misra, Shri R.R.	Sharma, Shri R. C
Ghosh, Shri M. K.	Murty, Shri M.S	Shobha Ram, Shri
Hajarnavis, Shri	Narasimhan, Shri	Singh, Shri Barbal
Hansda, Shri Subodh	Naskar, Shri P S	Singh, Shri D N
Jain, Shri A. P	Nayar, Dr. Sushila	Singh, Shri H.P
Jain, Shri M C	Negi, Shri Nek Ram	Singh, Shri Radha Mohan
Jinachandran, Shri	Nehru, Shri Jawaharlal	Singh, Shri Raghunath
Jogendra Sen, Shri	Neswi, Shri	Sinha, Shri Aniruddh
Khan, Shri Osman Ali	Pahadia, Shri	Sinha, Shri Gajendra Prasad
Khedkar, Dr G. B	Pandey, Shri K Neeni	Sinha, Shri Jhulan
Khwaja, Shri Jamal	Panna Lal, Shri	Sinha, Shri Satya Narayan
Kistaiya, Shri	Raj Bahadur, Shri	Sinatak, Shri Nardeo
Kottukapally, Shri	Ramaul, Shri S N.	Sonavane, Shri
Krishna Chandra, Shri	Rane, Shri	Subramanyam, Shri T
Kureel, Shri B N	Rao, Shri Jaganatha	Thomas, Shri A M
Laxmi Bai, Shrimati	Reddy, Shri Rami	Varma, Shri M L
Mahadeo Prasad, Shri	Roy, Shri Bishwanath	Vyas, Shri R C
Malviya, Shri Motilal	Rup Narain, Shri	Wadiwa, Shri

The motion was negatived.

Shri Sadhan Gupta (Calcutta-East): The sugar magnates have got it

Mr. Deputy-Speaker: The question is

"The at the end of the motion, the following be added, namely:—

and recommends—

(a) that Government do appoint a Committee consisting of a High Court Judge and two Members of Parliament one from each House to enquire into the undue profits earned by the sugar interests during the last few months'"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That at the end of the motion, the following be added, namely:

'and recommends—

(a) that a Committee consisting of five members of Parliament, three from Lok Sabha and two from Rajya Sabha, presided over by a Judge of High Court, be appointed to investigate and enquire into unduly high profits earned by the sugar industrialists during the last few years'"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: I will now put the motion of Shri Raghunath Singh

Shri Narayanankutty Menon: You may rule it out of order as it has no meaning

Mr. Deputy-Speaker: The Speaker has allowed it and it has been moved.

Now the question is:

'That for the original motion, the following be substituted, namely.

'This House expresses its concern at the rise in the sugar prices and after taking note of the steps already taken by Government recommends that Government should take such further steps as are found necessary from time to time to check the rise in the prices of sugar and profiteering by sugar interests."

The motion was adopted.